न्यू देहली पोस्ट

■ वर्ष 13 ■ अंक 23 रविवार (साप्ताहिक) 15 जून 2025 ■ पृष्ठ 16 ■ मूल्य 5 रुपये

जीत के जश्न में मौत का मातम

क्या जल समाधी लेंगे भारत के तीन शहर ?

नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी एनटीयू की टीम ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 48 तटीय शहरों का अध्ययन किया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कि विशेष रूप से समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण सबसे अधिक ख़तरा होने की आशंका है। इसका कारण मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन है। भारत के भी तीन प्रमुख शहर चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता के लगातार धंसने से करोड़ों लोगों की जिंदगी डेंजर जोन में आ गई है। जिस तेजी से इन शहरों का धंसान हो रहा है उससे इन शहरों के समुद्र में डूबने की सम्भावना ज्यादा बढ़ गई है।

अखिलेश अखिल

अभी हाल में सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी एनटीयू की एक स्टडी सामने आयी है जिसमे कहा गया है कि दुनिया के कई प्रमुख शहर तेजी से धंसान का सामना कर रहे हैं और समुद्र तल से नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। डेंजर जोन में पहुँच गए शहरों में जहाँ जकार्ता पहले नंबर पर आ गया है वही भारत के भी तीन प्रमुख शहर चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता के लगातार धंसने से करोड़ों लोगों की जिंदगी डेंजर जोन में आ गई है। जिस तेजी से इन शहरों का धंसान हो रहा है उससे इन शहरों के समुद्र में डूबने की सम्भावना ज्यादा बढ़ गई है।

भारत के इन तीन शहरों के करीब दो करोड़ लोगों के सामने विस्थापन की समस्या खड़ी हो रही है तो दुनिया के 48 शहरों के धंसने के आंकड़ों को अगर सामने रखा जाए तो करीब 16 करोड़ लोगों के ऊपर या तो मौत का साया मडरा रहा है या फिर इतनी बड़ी आबादी के सामने विस्थापन की समस्या खड़ी होती दिख रही है। दरअसल, नानयांग टेक्नोलॉजिकल

यूनिवर्सिटी यानी एनटीयू की टीम ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 48 तटीय शहरों का अध्ययन किया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कि विशेष रूप से समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण सबसे अधिक ख़तरा होने की आशंका है। इसका कारण मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन है। जहाँ भारत के शहरों के जमींदोज होने और समुद्र में समा जाने की बात है ,उसमे कोलकाता ,चेन्नई और अहमदाबाद का नाम सबसे ऊपर है। हालाँकि सूरत और मुंबई शहर भी धंसान और समुद्र में डूब जाने के कगार पर खड़ा है लेकिन भारत के तीन शहरों का जिस तेजी से धंसान जारी है ,उसने वैज्ञानिकों समेत आम लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। नासा के अनुसार, कोलकाता में 2024 में समुद्र के स्तर में 0.59 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन एनटीयू की हालिया स्टडी के अनुसार, 2014 से 2020 के बीच कोलकाता के कुछ हिस्सों में औसतन प्रति वर्ष 0.01 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर तक जमीन धंसी है।

शेष १ पर ➤➤➤

खतरनाक फंगस के साथ अमेरिका में अरेस्ट हुए दो चीनी नागरिक

न्यू देहली पोस्ट

अमेरिकी एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने खुलासा किया है कि एफबीआई ने 'फ्यूसैरियम ग्रैमिनियरम' नामक 'खतरनाक फंगस' की तस्करी के लिए 2 चीनी शोधकर्ताओं को अमेरिका में गिरफ्तार किया है। पटेल ने कहा ''मैं पुष्टि कर सकता हूं कि एफबीआई ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर देश में एक खतरनाक जैविक रोगजनक की तस्करी की थी।" फंगस की प्रकृति और इसके प्रभावों के बारे में बताते हुए, पटेल ने कहा, "युनकिंग जियान नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने 'फ्यूसैरियम ग्रैमिनियरम' नामक एक खतरनाक फंगस की तस्करी की है, जो एक कृषि-आतंकवाद एजेंट है, जिसे मिशिगन विश्वविद्यालय में शोध करने के लिए अमेरिका में लाया गया था, जहां वह काम करती है। यह फंगस 'हेड ब्लाइट' नामक बीमारी का कारण बन सकता है, जो गेहूं, जौ, मक्का और चावल की बीमारी है, जो मनुष्यों और पशुओं दोनों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है। यह हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर के आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है।" साक्ष्यों से पता चलता है कि जियान को चीनी सरकार से धन प्राप्त हुआ था।

एफबीआई निदेशक ने कहा कि साक्ष्यों से पता चलता है कि जियान ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी व्यक्त की और चीन में इस रोगजनक पर इसी तरह के शोध के लिए चीनी सरकार से धन प्राप्त किया। डेट्रायट की एक अमेरिकी अदालत में हाल ही में दो चीनी नागरिकों 33 वर्षीय युनकिंग जियन और 34 वर्षीय जुनयोंग लियू के खिलाफ गंभीर आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। इन पर षड्यंत्र रचने, अवैध रूप से खतरनाक सामान अमेरिका लाने, झूठे बयान देने और वीजा धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोप लगे हैं। लेकिन इस केस की सबसे डरावनी बात है तस्करी से लाई गई वो चीज जो एक खतरनाक फंगस है। फ्यूजेरियम ग्रैमिनी नाम का यह फंगस फसलों को बर्बाद कर देता है।

फसलों में बीमारी पैदा करने की चीनी साजिश?

मिशिगन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के एटॉर्नी ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फ्यूजेरियम ग्रैमिनी कोई साधारण फंगस नहीं, बल्कि वैज्ञानिक इसे कृषि आतंकवाद का संभावित हथियार मानते हैं। यह फसल में 'हेड ब्लाइट' नाम की बीमारी फैलाता है जिससे गेहूं, चावल, जौ और मक्का जैसी प्रमुख फसलें नष्ट हो जाती हैं। हर साल यह फंगस दुनियाभर में अरबों डॉलर का नुकसान करता है।

शेष १ पर ➤➤➤

यूक्रेन का रूस पर संहारक हमला, भारत के लिए चेतावनी, दुनिया को विश्व युद्ध की आशंका

यूक्रेन ने पिछले सप्ताह अब तक सबसे बड़ा ड्रोन हमला रूस पर किया है। यह हमला कोई मामूली नहीं है। इस हमले से दुनिया भर के देश चकित हैंऔर भयभीत भी। यूक्रेन के हमले से रूस के 41 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह हो गए। लेकिन असली कहानी यह नहीं है। असली कहानी तो हमें उस पर्ल हार्बर पर हमले की याद दिला रही है जिसके बाद अमेरिका ने जापान को तबाह ही कर दिया था। इस हमले के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ और जापान सरेंडर कर गया। क्या यूक्रेन के रूस पर इस घातक हमले के बाद रूस कहीं वही सब तो नहीं करने को विवश हो जाएगा ?

विशेष संवाददाता

यूक्रेन की तरफ से अब रूस पर बड़ा हमला किया गया है, जिसमें रूस के कई बमवर्षक विमानों को एक झटके में तबाह कर दिया गया। ये एक अचानक की गई एयरस्ट्राइक थी, जिसे रूस रोक नहीं पाया। अब इस हमले को अमेरिका के पर्ल हार्बर अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पर्ल हार्बर में आखिर हुआ क्या था...

यूक्रेन नहीं मान रहा हार : पहले बात रूस और यूक्रेन के युद्ध की करें तो ये लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन किसी भी तरह रूस के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। वहीं रूस भी यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच यूक्रेन के हवाई हमले ने तीसरे विश्वयुद्ध की घंटी एक बार फिर बजाई है। अब लोगों

को वो हमला याद आ रहा है, जिसने परमाणु हमले की तरफ पहला कदम बढ़ाने का काम किया था।

कैसे हुआ था पर्ल हार्बर अटैक? : ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब अमेरिका किसी भी हाल में इस विश्वयुद्ध में कूदना नहीं चाहता था। वहीं जापान को अमेरिका से खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए जापान के शासक ने अमेरिका पर हमला करने की योजना बनाई। जापान ने अमेरिका के बड़े बंदरगाह पर्ल हार्बर को अपना टारगेट चुन लिया, यहां अमेरिका के बड़े युद्धपोत और सैन्य ताकत हुआ करती थी। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान के कई विमानों ने एक साथ मिलकर पर्ल हार्बर पर बम बरसाने शुरू कर दिए। अमेरिका को इस हमले का अंदाजा भी नहीं था। इस हमले में अमेरिका के 300 से ज्यादा विमान तबाह हो गए और कई समुद्री जहाज भी नष्ट हुए। हमले में कुल 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई।

अमेरिका ने जापान के खात्मे की खाई कसम : इस बड़े हमले के बाद अमेरिका की तरफ से सीधे जापान के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही अमेरिका भी द्वितीय विश्वयुद्ध में कूद गया। अमेरिका ने जापान पर कई हमले किए, लेकिन उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाया।

शेष १ पर ➤➤➤

यूक्रेन का रूस पर...

इसके बाद जापान को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जापान ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। इसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। युद्ध की पहली नीति तो यही है कि सबसे पहरे् किसी पर भरोसा नहीं की जाए। भारत ने अमेरिका पर भरोसा ही तो किया था लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ क्या किया ? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका का खेल सामने आ चुका है। वह न भारत का है और नहीं पाकिस्तान का ही। वह बनिया देश है जो यही चाहता है कि दुनिया भर में युद्ध जारी रहे ताकि उसके हथियार बिकते रहें। जो उसके हथियार का ग्राहक नहीं वह उसका कोई नहीं।

इसी तरह यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को भी आप देख सकते हैं। यूक्रेन ने पिछले सप्ताह अब तक सबसे बड़ा ड्रोन हमला रूस पर किया है। यह हमला कोई मामूली नहीं है। इस हमले सक्से दुनिया भर के देश चकित हैं। यूक्रेन के हमले से रूस के 41 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह हो गए। लेकिन असली कहानी यही नहीं है। असली कहानी तो यह है कि यूक्रेन का यह भारी हमला तब हुआ है जब शांति वार्ता के प्रयास चल रहे थे। इस्ताम्बुल और रूस के बीच शांति वार्ता होनी थी। इसी बीच रूस पर इतना बड़ा हमला जाहिर है दबाब बनाने के लिए ही तो किया गया है। कुछ रिपोर्ट तो यह भी बता रही है कि आर्कटिक में स्थित रूस के परमाणु पनडुब्बी बेस सेवरमोर्स्क पर भी हमला किया गया है। यह बेस रूस की उत्तरी फ्लीट का मुख्यालय है। कोला प्रायद्वीप पर हुए विस्फोटों के बाद काले धुएं का वीडियो सामने आया है। लेकिन अभी सब कुछ साफ़ नहीं हुआ है।

ड्रोन का घातक हमला

यूक्रेन ने रूस पर हमला करके सिर्फ पुतिन को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि ड्रोन का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन ने रूस को ऐसा झटका दिया कि दुनिया के सारे सैन्य रणनीतिकारों की आँखें फटी की फटी रह गईं। वहीं भारत के लिए यह एक चेतावनी के साथ-साथ सबक भी है। 1 जून को यूक्रेन ने 'ऑपरेशन स्पाइडर वेब' के तहत रूस के पांच हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले किए। साइबेरिया के इरकुत्स्क जैसे दूर-दराज के इलाकों तक, जहां से यूक्रेन की सीमा 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक सस्ते FPV ड्रोन्स ने रूस के 41 बमवर्षक विमानों को आग के हवाले कर दिया। ये कोई रातोंरात की साजिश नहीं थी, बल्कि डेढ़ साल की चालाकी भरी प्लानिंग थी।

यूक्रेन के जासूस खेल में शामिल

संभव है कि रूस में यूक्रेन के जासूस खेल में शामिल होंगे। ड्रोन्स को ट्रकों में छिपे लकड़ी के केबिन्स में तस्करी कर रूस के भीतर पहुँचाया गया, और फिर रिमोट से छत खोलकर इन ड्रोन्स को उड़ाया गया। रूस के रणनीतिक बमवर्षक, जैसे Tu-95 और Tu-22M3, जो अब बनते भी नहीं, धू-धू कर जल उठे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने इसे 'खूबसूरती से जलता हुआ' बताया, और सचमुच, यह हमला युद्ध की किताबों में दर्ज होने लायक है।

सस्ते ड्रोन से बड़े हमले

यूक्रेन ने 117 छोटे-छोटे FPV ड्रोन, जिनकी कीमत 50 हजार रुपये से भी कम मानी जा रही है, उससे रूस के मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सटीक निशाने पर भेजा। ये ड्रोन्स ट्रकों में लदे लकड़ी के कंटेनरों से निकले. संभव है कि ड्राइवरों को भी पता न रहा हो कि वे क्या ढो रहे हैं। यूक्रेन ने पहले रूस को चकमा दिया, उनके विमानों को चुनिंदा हवाई अड्डों पर इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया, और फिर एक साथ धमाका कर दिया। रूस को इस हमले में 7 बिलियन डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है, जो कि कोई छोटी-मोटी बात नहीं है।

भारत के लिए चेतावनी की घंटी!

अब बात भारत की. यूक्रेन का यह हमला भारत के लिए चेतावनी जैसा है। भारत, जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ-साथ आतंकी खतरों से घिरा है, उसे इस हमले से सबक लेना होगा। हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए. पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तक फैले जासूसी नेटवर्क की खबरें दिखाती हैं कि पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश कर रहा है। हाल में मिले जासूसों के नेटवर्क इस खतरे की ओर इशारा करते हैं।

ड्रोन नया खतरा

ड्रोन अब युद्ध का नया चेहरा हैं। यूक्रेन ने साबित कर दिया कि सस्ते ड्रोन्स महंगे-महंगे विमानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भारत में भी ड्रोन का खतरा बढ़ रहा है। तस्करी से लेकर हथियार गिराने में इनका इस्तेमाल होता है। जम्मू-कश्मीर में ड्रोन हमले पहले ही देखे जा चुके हैं। अगर पाकिस्तान या कोई और इस तकनीक को और बढ़ाता है, तो भारत के लिए खतरा कई गुना बढ़ सकता है।

भारत को क्या करना चाहिए?

भारत को अपनी ड्रोन तकनीक को और उन्नत करना होगा। सस्ते, सटीक और लंबी दूरी के ड्रोन्स विकसित करने चाहिए। ताकि अगर दुश्मन ऐसी गलती करने की सोचे तो उसे उसी के अंदाज में जवाब दे सकें। हाल ही कई भारतीय मिले जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। पाकिस्तानी जासूसों का नेटवर्क तोड़ने के लिए खुफिया एजेंसियों को और सक्रिय करना होगा। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर नजर रखनी होगी। ड्रोन हमलों से बचने के लिए भारत को एंटी-ड्रोन सिस्टम और साइबर सुरक्षा को अपग्रेड करना होगा। यूक्रेन ने दिखाया कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना संभव है। भारत को भी ऐसी आक्रामक रणनीति पर विचार करना चाहिए, खासकर आतंकी ठिकानों के खिलाफ।

खतरनाक फंगस के...

इससे पैदा होने वाले टॉक्सिन्स इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। इसके कारण उल्टी, लिवर डैमेज और प्रजनन प्रणाली पर असर जैसे प्रभाव देखे जा सकते हैं। FBI डायरेक्टर कश पटेल ने भी चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

सीसीपी के सदस्य को चीनी सरकार से मिला फंड

शिकायत में दावा किया गया है कि युनकिंग जियन को चीन सरकार से इस फंगस पर काम करने के लिए फंड मिला था। उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से यह भी पता चला कि वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य हैं और पार्टी के प्रति उसकी गहरी निष्ठा है। यही नहीं, उसका प्रेमी जुनयोंग लियू भी एक चीनी यूनिवर्सिटी में इसी फंगस पर रिसर्च करता है। उसने कबूल किया है कि उसने यह फंगस डेटायट एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका में तस्करी किया। यह प्रयोग मिशिगन विश्वविद्यालय की एक लैब में जियन के साथ रिसर्च करने के उद्देश्य से किया गया।

अमेरिका के लैब में चीन का षडयंत्र?

संघीय अभियोजक जेरोम एफ. गोरगन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का दिल कहे जाने वाले मिशिगन की प्रयोगशाला मेंएग्रो टेररिज्म को अंजाम देने की साजिश चलाई जा रही थी। यदि यह योजना सफल होती तो अमेरिका की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को बड़ा झटका लग सकता था।

एफबीआई और सीबीपी ने दिखाई सतर्कता

एफबीआई के डेट्रायट ऑफिस के स्पेशल एजेंट इन चार्ज चेवोरिया गिब्सन ने बताया कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने स्थानीय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला का दुरुपयोग करते हुए जैविक खतरे की तस्करी की, जो आम जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। वहीं, कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के डायरेक्टर मार्टी सी. रेबन ने इसे 'कृषि और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए एक विनाशकारी खतरा' बताया।

आरोपियों पर चलेगा मुकदमा

जियन को आज डेट्रायट की संघीय अदालत में पेश किया जाना है। हालांकि, अभी केवल शिकायत दर्ज हुई है और आरोप साबित होने बाकी हैं। यह तय होना अभी बाकी है कि इनके खिलाफ फेलोनी चार्ज में मुकदमा चलेगा या नहीं। फिलहाल एफबीआई और सीबीपी इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। यह मामला न केवल जैविक तस्करी का है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर हो रही गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नया मोर्चा बन रही हैं? जब प्रयोगशालाएं हथियार बन जाएं, तो सत

सांसद महुआ मोइत्रा ने जर्मनी में की गुपचुप शादी

न्यूज़ डेस्क

द टेलीग्राफ ऑनलाइन द्वारा प्राप्त एक तस्वीर में, महुआ मोइत्रा को जर्मनी में मुस्कुराते हुए, सोने से सजे हुए देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक दो बार से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने 3 मई को चुपचाप शादी कर ली। आप इसे दूसरा ऑपरेशन सिंदूर कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी और सांसद ने कृष्णानगर की सांसद की शादी के बारे में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बाद सरकार ऑपरेशन सिंदूर का सच बताने को तैयार नहीं है ठीक वैसे ही महुआ की शादी को लेकर टीएमसी मौन व्रत धारण किये हुए है।

शादी के बारे में पूछे जाने पर एक तृणमूल सांसद ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "मुझे इसकी जानकारी नहीं है।" महुआ के पति का नाम पिनाकी मिश्रा है, जो बीजू जनता दल के भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने पुरी से लोकसभा सांसद के रूप में कार्य किया है। 1996 में पिनाकी मिश्रा पुरी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और तत्कालीन पुरी सांसद और केंद्रीय मंत्री ब्रज किशोर त्रिपाठी को हराया था । मिश्रा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उन्होंने भारत के लगभग सभी उच्च न्यायालयों और भारत के प्रमुख न्यायाधिकरणों में मुकदमे लड़े हैं। मिश्रा ने सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली से बीए (ऑनर्स) इतिहास और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है । उनकी पहली शादी संगीता मिश्रा से हुई थी। अब, उन्होंने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से शादी की है। पहली शादी से उन्हें एक बेटा और एक बेटी है।

इधर ,सबसे मुखर सांसदों में से एक, महुआ मोइत्रा ने पहले डेनिश फाइनेंसर लार्स ब्रोरसन से शादी की थी, जिनसे उन्होंने तलाक ले लिया था । वह लगभग तीन साल तक अधिवक्ता जय अनंत देहाद्रई के साथ रिश्ते में थीं, जिन्हें बाद में उन्होंने "धोखा दिया गया पूर्व" बताया था। महुआ का सांसद के रूप में पहला कार्यकाल तब छोटा हो गया था जब उन पर व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ उनके एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा उकसाए जाने पर सवाल उठाने का आरोप लगाया गया था।नवंबर 2023 में, जब संसद उन्हें निष्कासित करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, तब महुआ ने द गार्जियन से कहा था, "पुरुषों में मेरी पसंद बहुत खराब है।" लेकिन अब फिर से 'द टेलीग्राफ' की एक रिपोर्ट के मुताबिक महुआ और पिनाकी चुपचाप जर्मनी में शादी के बंधन में बंध गए हैं। टीएमसी की तरफ से अभी तक इस मामले पर किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है। महुआ अपने राजनीतिक जीवन के साथ-साथ निजी जीवन को लेकर भी चर्चा में रही हैं।

क्या जल समाधी लेंगे...

यानी पिछले छह वर्षों में कोलकाता लगभग 12 सेंटीमीटर से ज्यादा धंस गया है और समुद्र तल के करीब पहुँच गया है।बड़ी बात यह है कि धंसते हुए क्षेत्रों में 90 लाख लोग रहते हैं। एनटीए की स्टडी के मुताबिक कोलकाता के सबसे तेजी से धंसने वाले क्षेत्रों में से एक भाटपारा था, जहां हर साल 2.6 सेंटीमीटर जमीन धंस रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि कोलकाता में भूमि धंसने का कारण भूजल का अत्यधिक दोहन करना है। एक्सपर्ट चेतावनी देते हुए कहते हैं कि कोलकाता में जिन क्षेत्रों में जमीन धंस रही है, वहां भूकंप और बाढ़ का ख़तरा अधिक है। अजर यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा हादसा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती।

उधर दक्षिण के प्रमुख शहर चेन्नई में के कुछ हिस्सों में 2014 से 2020 के बीच जमीन हर साल 0.01 सेंटीमीटर से 3.7 सेंटीमीटर तक धंसी है। इन धंसते हुए क्षेत्रों में 14 लाख (1.4 मिलियन) लोग रहते हैं। एनटीए की स्टडी के मुताबिक, चेन्नई शहर में सबसे तेज़ी से धंसते हुए क्षेत्रों में से एक थरमणि है। यहां जमीन औसतन प्रति वर्ष 3.7 सेंटीमीटर धंसी है। यानी की पिछले छह साल में करीब डेढ़ फ़ीट का धंसान हुआ है। उधर नासा के अनुसार चेन्नई में 2024 में समुद्र के स्तर में 0.59 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि चेन्नई के उन क्षेत्रों में तेजी से भूमि धंस रही है, जहां कि कृषि, औद्योगिक और घरेलू गतिविधियों के लिए भारी मात्रा में भूजल का दोहन किया गया है।

अहमदाबाद की कहानी तो और भी भयावह है। एनटीयू की स्टडी के अनुसार, 2014 से से 2020 के बीच अहमदाबाद के कुछ हिस्सों में जमीन औसतन प्रति वर्ष 0.01 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर तक धंसी है। इन धंसते हुए क्षेत्रों में 51 लाख लोग लोग रहते हैं। एनटीयू की स्टडी में सामने आया है कि अहमदाबाद में सबसे तेजी से धंसते हुए क्षेत्रों में से एक पिपलाज है और यहां जमीन हर साल औसतन 4.2 सेंटीमीटर धंस रही थी। वहीँ नासा के मुताबिक 2024 में समुद्र के स्तर में 0.59 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जमीन के धंसने का कारण पंपिंग के ज़रिए भूजल से अत्यधिक पानी निकालना, समुद्र का बढ़ता स्तर और अधिक बारिश होना है. ऐसा ही रहा तो भविष्य में शहर में बाढ़ का ख़तरा बढ़ जाएगा। एनटीयू का स्टडी चीन और इंडोनेशिया के लिए भयावह तस्वीर पेश करता दीखता है। स्टडी के मुताबिक़ सबसे गंभीर जमीन धंसने का मामला चीन के तियानजिन का है। यहां तेजी से औद्योगिक और बुनियादी विकास हुआ है। साल 2014 से 2020 के बीच शहर के सबसे अधिक प्रभावित हिस्से में औसतन हर साल 18.7 सेंटीमीटर जमीन धंसी है। इसका कारण यह है कि यहां की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और विकास भी बहुत हो रहा है। पानी की मांग कहीं ज़्यादा है। इसी तरह जकार्ता का लगभग आधा हिस्सा अब समुद्र स्तर से नीचे स्थित है। यह शहर दलदली भूमि पर बसा है, जहाँ 13 नदियां समुद्र में मिलती हैं, जिससे यह क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है। जकार्ता के कुछ हिस्से 1970 की तुलना में 4 मीटर नीचे आ चुके हैं। इस कारण इंडोनेशिया ने नूसंतारा को नई राजधानी के रूप में विकसित करने का फ़ैसला लिया है।

बेंगलुरु भगदड़ :आरसीबी और केसीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बेंगलूर के चिन्नावस्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कर्नाटक क्रिकेट एशोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इस भगदड़ में 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो बगै।

राजनीतिक डेस्क

बेंगलूर भगदड़ में 11 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने के बाद देश में राजनीतिक तूफ़ान भी खड़ा हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अब बीजेपी भगदड़ को लेकर हमला कर रही है। इस खेल का अंत कहा होगा यह तो अभी पता नहीं है लेकिन भगदड़ को लेकर पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई है। आरसीबी और केसीए के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरसीबी ने 3 जून को आईपीएल का अपना पहला खिताब जीता था, जिसके बाद टीम की विक्टू परेड निकालने की बात सामने आई थी। 4 जून को सुबह से ही सड़कों पर भीड़ उमड़ने लगी। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने विक्ट्री परेड की परमिशन नहीं दी और इसे कैंसिल कर दिया गया। पुलिस ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए उस जश्न को भी स्थगित करने का अनुरोध किया था। उनका मानना था कि अभी फैंस में बहुत उत्साह है, क्योंकि एक दिन पहले ही टीम ने ट्रॉफी जीती है।

आरसीबी 4 जून को ही करना चाहती थी कार्यक्रम

पुलिस चाहती थी कि आरसीबी ये प्रोग्राम रविवार (8 जून 2025) को आयोजित करे, लेकिन आरसीबी ने तर्क दिया था कि उनके विदेशी खिलाड़ी अपने देश लौट जाएंगे इसलिए वे 4 जून को ही कार्यक्रम रखना चाहते हैं। बेंगलुरु के शहरी उपायुक्त जी जगदीश ने इससे पहले कहा कि भगदड़ की घटना की जांच में शामिल होने के लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुलिस आयुक्त बी दयानंद को नोटिस जारी किया जाएगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

चिन्नास्वामी स्टेडियम का निरीक्षण किया जहां बुधवार को भगदड़ मची थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार (4 जून 2025) को मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इस भगदड़ का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। उसने जिला प्रशासन और पुलिस को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी के अनुसार यह आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों की ओर से भीड़ को नियंत्रण करने का प्रबंधन खराब था और हैरानी की बात यह है कि त्रासदी होने और स्टेडियम के बाहर शव पड़े होने के बावजूद स्टेडियम के अंदर उत्सव और जश्न जारी रहा। एनएचआरसी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की और उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, पीड़ितों को मुआवजा और न्याय दिलाने का अनुरोध किया।

न्यू देहली पोस्ट
9-15 जून 2025
प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक आशीष कुमार द्वारा 262 ए ,सेक्टर 4 ,वैशाली ,गाजियाबाद से प्रकाशित,एवं एचटी मीडिया लिमिटेड ,प्लाट नंबर 8 ,उद्योग विहार ,ग्रेटर नोएडा ,गौतमबुद्ध नगर ,उत्तर प्रदेश -201306 से मुद्रित. **RNI NO . UPHIN /2013 /49239**
संपादक : आशीष कुमार, **प्रसार प्रबंधक** : दशरथ सिंह. **संपादकीय कार्यालय** : 614 टावर बी ,6ठी मंजिल ,नोएडा वन बिल्डिंग ,सेक्टर 62 ,नोएडा ,गौतमबुद्ध नगर ,यूपी -201309. **ईमेल नंबर** -postnewdelhi @gmail.com

संपादकीय

हार्वर्ड में विदेशी छात्रों की नो-एंट्री का भारत पर असर

अमेरिका की ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड में पढ़ाई का सपना देख रहे विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने के इच्छुक लगभग सभी विदेशी छात्रों का देश में प्रवेश रोकने के लिए एक शासकीय आदेश पर साइन किए हैं।बता दें कि ट्रंप सरकार का कदम 'आइवी लीग स्कूल' से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दूर रखने का उनका नया प्रयास है। 'आइवी लीग' हार्वर्ड विश्वविद्यालय समेत अमेरिका के आठ प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों का समूह है। ट्रंप ने घोषणा की गई है कि हार्वर्ड को मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज स्थित अपने परिसर में विदेशी छात्रों को दाखिला देने की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। ट्रंप ने आदेश में लिखा, ''मैंने यह तय किया है कि उक्त वर्णित विदेशी नागरिकों के वर्ग का प्रवेश अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक है क्योंकि मेरे विचार में हार्वर्ड के आचरण ने इसे विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त गंतव्य बना दिया है।''

अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के इस आदेश का भारतीय छात्रों पर क्या असर पड़ेगा ? बता दें कि भारत अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा सोर्स है। एकेडमिक वर्ष 2023–24 में 3.31 लाख से अधिक भारतीय छात्र नॉमिनेटेड थे। इनमें से बड़ी संख्या में छात्र हार्वर्ड जैसी आइवी लीग संस्थानों में पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अब ट्रंप के खेल से बड़ी संख्या में उन भारतीय छात्रों को झटका लग सकता है जो अमेरिका जाकर ऊँची शिक्षा पाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप के फैसले का भारतीय छात्रों पर कई तरह से असर पड़ सकता है जैसे कि जो छात्र हार्वर्ड में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उन्हें वीज़ा मिलने में देरी या नामंजूरी का सामना करना पड़ सकता है। भले ही उनका एडमिशन हो चुका हो और फीस भी भर दी हो। इसके साथ ही वर्तमान में हार्वर्ड में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का वीजा स्टेटस खतरे में पड़ सकता है और उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।

इतना नहीं नहीं इस अनिश्चितता के चलते स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट के अवसर भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कानूनी स्थिति और क्लास अटेंडेंस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। और छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों को फीस रिफंड, सुरक्षा और भविष्य की योजना को लेकर भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ट्रंप सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? माना जाता है कि यह देश के सबसे पुराने और सबसे धनी विश्वविद्यालय के साथ 'व्हाइट हाउस' के टकराव की दिशा में एक और कदम है। बोस्टन की एक संघीय अदालत ने हार्वर्ड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर रोक लगाने से गृह सुरक्षा विभाग को पिछले सप्ताह रोक दिया था लेकिन ट्रंप का आदेश एक अलग कानूनी प्राधिकार का इस्तेमाल करता है। ट्रंप ने एक व्यापक संघीय कानून का हवाला दिया है जो राष्ट्रपति को उन विदेशियों को रोकने का अधिकार देता है जिनका प्रवेश ''अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक'' हो सकता है। उन्होंने इसी प्राधिकार का हवाला देते हुए यह भी घोषणा की कि 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक रहेगी तथा सात अन्य देशों के नागरिकों पर भी कुछ पाबंदियां होंगी।

नीतीश का सवर्ण और मौलाना पर चुनावी दांव

बिहार चुनाव को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है। एक तरफ उन्होंने सवर्ण समाज को साधने के लिए सवर्ण आयोग का गठन किया है तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन भी किया है और अपने खास नेता को अध्यक्ष बना दिया है। बिहार की राजनीति में नीतीश का यह दांव कितना कारगर होगा यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।

अखिलेश अखिल

नीतीश कुमार भले ही सेहत से कमजोर दिख रहे हों लेकिन राजनीति के वे पक्के खिलड़ाइ भी हैं। ऐसा खिलाडी जिसके खेल के बारे शायद ही कोई जाने। कब किसे मात देनी है और कब किसके गाला लगाना है यह सब समय और स्थान के जरिये नीतीश कर लेते हैं। नीतीश जानते हैं कि बीजेपी का भी अपना खेल है। बीजेपी के बारे में स्वे और भी बहुत कुछ जानते हैं और वे यह भी जानते हैं कि अगले चुनाव में क्या कुछ हो सकता है और बीजेपी क्या कुछ खेल कर सकती है। लेकिन राजनीति में बहुत कुछ सहना भी पड़ता है और वक्त का इन्तजार भी करना होता है। नीतीश कुमार जदयू को जिताने के लिए वह सब करते नजर आ रहे हैं जो वे अब तक करते रहे हैं। जदयू की कोशिश यही है कि वह इस बार बड़ी पार्टी बन कर उभरे। इसके लिए जदयू के पास तर्क भी है और नीतीश का चेहरा भी। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जितना संभव हुआ ,किया भी है। लेकिन अब शायद बीजेपी उन्हें सहने को तैयार नहीं। लेकिन नीतीश अपने दांव से भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

यही वजह है कि बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने सवर्ण जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन किया है। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह को आयोग का अध्यक्ष और जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में भले ही साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहां सियासी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। सीएम नीतीश सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। यही कारण है कि वे चुनावी साल को देखते हुए कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही वे सभी वर्गो को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। जेडीयू नेता गुलाम रसूल को बिहार का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है।

सीएम नीतीश का ये फैसला सवर्ण वर्ग के हितों को साधने और उनकी आवाज़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। यह नियुक्ति आगामी चुनावों में दोनों पार्टियों की सहयोगात्मक रणनीति को दर्शाती है। सीएम नीतीश ने इससे पहले साल 2011 में सवर्ण आयोग बनाया था, हालांकि कुछ कारणों के चलते उसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया था। सीएम नीतीश ने जो आयोग बनाया है, उसका काम सवर्ण वर्ग के मुद्दों को उठाना और उनका समाधान होगा। सीएम नीतीश के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो ये सब चुनावी प्रयोग है। सीएम नीतीश हर वर्ग को अपनी ओर लाना चाहते हैं। इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। उधर मुस्लिमों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने मौलाना दांव भी खेला है। नीतीश सरकार ने 11 सदस्यीय बिहार अल्पसंख्यक आयोग का पुर्नगठन किया है। जेडीयू के महासिचव और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुलाम रसूल बलियावी बिहार में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं ,वे वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जेडीयू में रहते हुए भी आक्रामक तेवर अपना रहे हैं। इसी के चलते अब मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने उन पर बड़ा दांव खेला है।

वक्फ संशोधन कानून पर मोदी सरकार का समर्थन करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटबैंक को नाराज कर दिया है। विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश को देखते हुए जेडीयू अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मौलाना बलियावी जेडीयू के लिए राजनीतिक मददगार साबित होंगे ? बिहार में जाति सर्वे के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी करीब 19 फीसदी के करीब है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं। इसके बाद सिख, बौद्ध और जैन समुदाय की आबादी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर आयोग में नियुक्ति की है। बिहार में करीब 17.7 फीसदी मुस्लिम आबादी है, जो सियासी तौर पर काफी अहम माने जाते हैं। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से करीब 48 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटरों का रोल काफी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम आबादी 20 से 40 प्रतिशत या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं, जहां 40 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और 7 सीटों पर 30 फीसदी से ज्यादा हैं।

सूबे की 30 सीटों पर 20 से 30 फीसदी के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल के इलाके में खासकर किशनगंज में मुस्लिम वोटर 70 फीसदी से भी ज्यादा है। इस लिहाज से मुस्लिम समुदाय बिहार चुनाव में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी अहमियत को देखते हुए माना जा रहा है कि वक्फ कानून का बिहार की राजनीति पर अच्छा-खासा प्रभाव पड़ सकता है। वक्फ बिल संसद से पास कराने में अहम रोल नीतीश कुमार की जेडीयू का रहा था। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि नीतीश कुमार अगर नहीं साथ देते तो मोदी सरकार वक्फ बिल संसद से पास नहीं करा पाती। इस बात को लेकर मुस्लिम संगठन लगातार जेडीयू के खिलाफ सियासी माहौल बनाने में जुटे हैं। नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव से पहले तक मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है, लेकिन 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद मुस्लिमों का जेडीयू से मोहभंग हो गया। हालांकि, 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को देखें तो मुस्लिमों का 5 फीसदी वोट ही जेडीयू को मिला है। ऐसे में गुलाम रसूल बलियावी के लिए मुस्लिमों का दिल जीतना आसान नहीं है, क्योंकि आरजेडी से लेकर कांग्रेस और ओवैसी तक मुस्लिम सियासत पर खुलकर खेल रहे हैं।

जाति गणना के साथ ही दो चरणों में जनसंख्या जनगणना का ऐलान

वरिष्ठ संवाददाता

केंद्र सरकार देश में जाति जनगणना का ऐलान पहले ही कर चुकी है। अब सरकार ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। सूत्रों को मुताबिक, भारत में 1 अक्टूबर 2026 से जाति गणना के साथ जनगणना शुरू होगी। यह जनगणना देशभर में दो चरणों में कराई जाएगी। बता दें कि, जनगणना 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती थी (2021 में कोरोना महामारी के कारण टली)। जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ-साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को भी अपडेट करने का काम बाकी है।

सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी राज्यों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू होगी। वहीं मैदानी इलाकों में जातीय जनगणना की शुरुआत 1 मार्च 2027 में होगी। साल 2026 में जनगणना के बाद से भविष्य में जनगणना का चक्र बदल जाएगा। जो पहले 1951 से शुरू हुआ था वो बदलकर 2027-2037 और फिर 2037 से 2047 हो जाएगी। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार, उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के इरादे की अधिसूचना 16 जून 2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।बता दें कि भारत की जनगणना,जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

गृह मंत्रालय बताया कि, 'जातियों की गणना के साथ-साथ दो चरणों में जनसंख्या जनगणना-2027 आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जनसंख्या जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च, 2027 के पहले दिन 00:00 बजे होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के गैर-समकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए, संदर्भ तिथि अक्टूबर, 2026 के पहले दिन 00.00 बजे होगी। उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के इरादे की अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार 16.06.2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।' भारत में हर दस साल में जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1947 में आजादी मिलने के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जबकि लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और साक्षरता दर 74.04 फीसदी था।

कांग्रेस बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी

न्यूज़ डेस्क

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, जो पिछले तीन साल से स्थगित थे। वैसे तो महाराष्ट्र के सभी शहरों के चुनाव अहम है लेकिन बृहन्नमुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी का चुनाव सबसे खास है। यह देश की सबसे धनी नगरपालिका है और पिछले कई दशकों से इस पर शिव सेना का कब्जा रहा है। लेकिन अब शिव सेना विभाजित हो गई है और उसके विभाजन के बाद पहला चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र में लगातार डेढ़ दशक तक कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रही तब भी दोनों मिल कर शिव सेना को नहीं हरा पाए।

इस बार कांग्रेस और एनसीपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वह बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। वैसे भी शरद पवार और उनके परिवार का असर मुंबई में कम है और पुणे के इलाके में ज्यादा है, जैसे एकनाथ शिंदे का असर ठाणे में है। इसलिए भाजपा ने बीएमसी चुनाव के लिए शिंदे और अजित पवार को ज्यादा भाव नहीं दिया है। ऐसे ही कांग्रेस भी शरद पवार की पार्टी को भाव नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि शरद पवार की पार्टी ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वह भाजपा के साथ जा सकती है। हालांकि यह तय नहीं है कि अजित पवार और शरद पवार की पार्टियों का विलय होगा या शरद पवार अलग से अपनी डील करके अपनी पार्टी का तालमेल भाजपा के साथ करेंगे। इसलिए भी कांग्रेस उनसे दूरी बना रही है।

विपक्ष की विशेष सत्र बुलाने की मांग ख़ारिज 21 जुलाई से चलेगा संसद का मॉनसून सत्र

राजनीतिक डेस्क

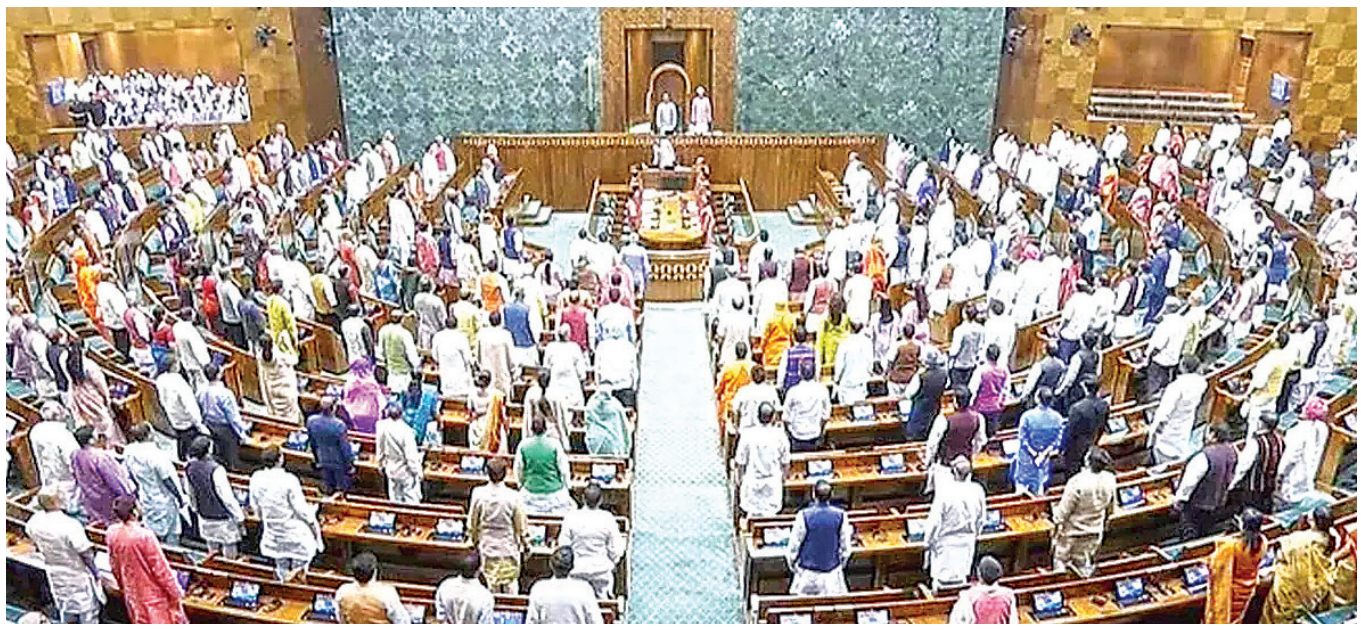

मो दी सरकार ने विपक्ष की उस मांग को ख़ारिज कर दिया है जिसमे पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। अब संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलाने की ऐलान किया गया है।केंद्रीय मंत्री रीजीजू ने विपक्ष की विशेष सत्र बुलाने की मांग के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मॉनसून सत्र में नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इससे साफ हो गया कि विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाने की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है।

'विशेष बैठक की मांग से बचने के लिए मानसून सत्र का ऐलान'

सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आमतौर पर संसद सत्र की तारीखों की घोषणा कुछ दिन पहले की जाती है। लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से 47 दिन पहले ही तारीखों का ऐलान कर दिया गया- ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह निर्णय मोदी सरकार ने केवल इसलिए लिया है ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन द्वारा बार-बार उठाई जा रही तत्काल विशेष बैठक की मांग से बचा जा सके।

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस सहित इंडिया ब्लॉक के विभिन्न दलों ने संसद की एक तत्काल बैठक बुलाकर निम्नलिखित राष्ट्रीय महत्व के गंभीर मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता जताई है।जिन मुद्दों पर विपक्ष बात करना चाहता है उनमे शामिल है पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमलों के लिए जिम्मेवार,आतंकवादियों को अब तक न्याय के कटघरे में लाने में विफलता,ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव और उसके बाद उत्पन्न हालात,ऑपरेशन सिंदूर का स्पष्ट राजनीतिकरण,सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा किए गए अहम खुलासे ,भारत को पाकिस्तान के साथ एक ही श्रेणी में रखे जाने की गंभीर और चिंताजनक कूटनीतिक स्थिति ,पाकिस्तान की वायुसेना में चीन की गहरी और खतरनाक घुसपैठ के स्पष्ट प्रमाण ,राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर बार-बार किए जा रहे दावे और विदेश नीति और कूटनीतिक स्तर पर सरकार की लगातार होती विफलताएं।

मानसून सत्र के दौरान भी ये तमाम मुद्दे, जो राष्ट्रहित में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, चर्चा के केंद्र में रहेंगे। प्रधानमंत्री ने भले ही विशेष सत्र से खुद को अलग रखा हो, लेकिन छह सप्ताह बाद उन्हें इन कठिन सवालों का जवाब देना ही होगा।

इससे पहले गुरुवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में शामिल 16 दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। बैठक खत्म होने के बाद इस संबंध में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाकारी दी थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया था। हमारी मांग थी कि एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाए, जिसके माध्यम से हम हमारी सेनाओं का धन्यवाद कर सकें और सरकार इस पूरे मामले पर अपनी बात रख सके। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम चाहते थे सरकार 'ऑपरेशन सिंदूर' से लेकर अमेरिका द्वारा सीजफायर की घोषणा, पाकिस्तान को वैश्विक तौर पर अलग करने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखें और रणनीतिक चर्चा करें।

संसद के विशेष सत्र के नाम पर इंडिया गठबंधन की एकता का प्रदर्शन

राजनीतिक डेस्क

आखिरकार संसद के विशेष सत्र की मांग के बहाने ही इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हो गई। काफी लम्बे समय के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक तब हुई है जब कांग्रेस के भी कई नेता कहते दिखे कि इंडिया गठबंधन का अब कोई वजूद नहीं बचा है। लेकिन जिस अंदाज में इंडिया के जुड़े नेता एक साथ होने का प्रदर्शन किया है वह मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है।

आ खिरकार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई पिछले सप्ताह हो ही गई। यह बैठक इस मायने में काफी अहम है जब इंडिया के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। पहलगाम हमले अजर फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद के विशेष सत्र की मांग को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर संयुक्त रूप से एक विशेष संसद सत्र की मांग की है।

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया था। हमारी मांग थी कि एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाए, जिसके माध्यम से हम हमारी सेनाओं का धन्यवाद कर सकें और सरकार इस पूरे मामले पर अपनी बात रख सके। हुड्डा ने कहा कि हम चाहते थे सरकार 'ऑपरेशन सिंदूर' से लेकर अमेरिका द्वारा सीजफायर की घोषणा, पाकिस्तान को वैश्विक तौर पर अलग करने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखें और रणनीतिक चर्चा करें।उन्होंने कहा कि जब सरकार दूसरे देशों में अपनी बात रख रही है तो देश की संसद में भी यह सारी बातें रखी जाए, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं संसद से जुड़ी हुई है। आज इस पत्र के माध्यम से सभी दलों के नेताओं ने इस मांग को दोहराया है।

इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, "हमने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है, उस पर 16 राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर हैं। यह कोई सामान्य पत्र नहीं है। विपक्ष जनता की आवाज है। हम चाहते हैं कि देश में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उस पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो आप विपक्ष के बार-बार अनुरोध के बाद भी विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे? क्या हमें विशेष सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? वहीं, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिनों में 13 बयान दिए और उन बयानों से भारत की भावनाएं आहत हुई हैं। एक समुदाय और एक राष्ट्र के तौर पर हम आहत हैं और इसके लिए संसद बुलाई जाती है। यह पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, यह जवाबदेही का मामला है।"

बैठक में 16 दल शामिल, आप, NCP (शरद) नहीं पहुंची

बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस , द्रविड़ मुनेत्र कड़गम , शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रीय जनता दल , जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी , रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी , झारखंड मुक्ति मोर्चा , विदुथलाई चिरुथैगल काची , केरल कांग्रेस, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम , और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन शामिल हुईं। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलिगेशन को वर्ल्ड टूर पर भेजा है। इस हफ्ते के अंत तक सभी डेलिगेशन वापस भारत लौट जाएंगे। विपक्ष उनके लौटने के बाद अगले हफ्ते विशेष सत्र में इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है।

खड़गे ने क्या कहा ?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने शनिवार को एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को स्पष्ट करने के बजाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं।'

खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करने की शर्तें क्या थीं। क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं? सीजफायर एग्रीमेंट की शर्तें क्या हैं? 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को यह जानने का हक है।'

सीडीएस का बयान

सीडीएस के बयान के बाद विशेष सत्र की मांग तेज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर ब्लूमबर्ग से बात की थी। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे? कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में सीडीएस अनिल चौहान का इंटरव्यू क्लिप शेयर करते हुए लिखा- इस बयान में यह माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? इस तरह के कई सवालों के जवाब के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।

ममता ने क्या कहा ?

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश के लोगों को संघर्ष के बारे में जानने का हक है। कांग्रेस के अलावा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं भारतीय डेलिगेशन के वापस लौटने के बाद केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील करती हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि देश के लोगों को हाल के संघर्ष और घटनाक्रम के बारे में किसी और से पहले जानकारी पाने का सबसे बड़ा अधिकार है।'

क्या है ऑपरेशन सिंदूर? : 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने 26 टूरिस्ट्स की हत्या की थी। इसका बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की। साथ ही बॉर्डर इलाकों में ड्रोन हमलों की भी कोशिश की। जवाब में, भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस मशीनरी, रडार इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सेंटर पर हमले किए और उन्हें नष्ट कर दिया।भारतीय हमले ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद, 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए सीजफायर की घोषणा की गई।

सिंदूर का राष्ट्रवादी खेल और सेना की चेतावनी

न्यूज़ डेस्क

ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, जो समय पर पूरा हुआ हो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि डेडलाइन नहीं पूरी होगी, फिर भी झूठे वादे किए जाते हैं।" "तेजस MK1 की डिलीवरी में देरी हो रही है। तेजस MK2 का प्रोटोटाइप अभी तक नहीं बना। स्टेल्थ AMCA फाइटर का भी कोई प्रोटोटाइप नहीं है। हमें सिर्फ रक्षा उत्पादन की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि डिजाइनिंग पर भी ध्यान देना होगा। सेना और उद्योग के बीच विश्वास की जरूरत है। हमें आज जो चाहिए, वह आज चाहिए।" ये शब्द हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह के जो 29 मई को दिल्ली में सीआईआई के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। बड़ी बात तो यह है कि जब एयर चीफ मार्शल बोल रहे थे तो बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौन साधे बैठे थे।

जाहिर है कि एयर चीफ मार्शल के इस बयान से यह तो साफ़ हो गया है कि मौजूदा समय में देश की क्या स्थिति है और सरकार क्या कुछ कर रही है। एयर चीफ मार्शाल का यह बयान सरकार की प्राथमिकता पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन सरकार को इन सवालों से कितना मतलब है यह सब इससे पता चलता है कि जहाँ सरकार को जल्द से जल्द इन सवालों का जवाब देना चाहिए और रक्षा उत्पाद की कमी को पूरा करनी चाहिए न कि सरकार को सेना और सिंदूर के नाम पर देश के भीतर चुनावी राजनीति को हवा देने चाहिए।सच तो यही है कि एयर चीफ़ मार्शल अगर चिंता जता रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर इन कमियों पर निगरानी करते लेकिन वे चुनावी रोड शो में मशगूल हैं।

देश में हथियार और उपकरण की स्थिति

आर्टिलरी: 155 मिमी अल्ट्रा-लाइट होवित्जर की आपूर्ति में देरी। बोफोर्स और धनुष तोपें हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं।

टैंक: T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक मौजूद हैं, लेकिन पुराने T-72 टैंकों का आधुनिकीकरण धीमा।

गोला-बारूद: 2017 की CAG रिपोर्ट में कहा गया कि 40% गोला-बारूद युद्ध में 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा।

विशेषज्ञों की चेतावनी

2017: CAG ने गोला-बारूद की कमी को "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" बताया।

2022: पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत ने बजट की कमी की ओर इशारा किया।

2025: रक्षा विशेषज्ञ लक्ष्मण बेहरा ने आधुनिकीकरण बजट में 0.9% कमी की आलोचना की।

वायु सेना

लड़ाकू विमान: 42 स्क्वाड्रन (756 विमान) चाहिए, लेकिन केवल 31 स्क्वाड्रन (558 विमान) उपलब्ध। मिग-21 और जगुआर पुराने हो चुके हैं।

तेजस और राफेल: तेजस की डिलीवरी में देरी, क्योंकि अमेरिकी जेट इंजन की आपूर्ति रुकी है। केवल 36 राफेल खरीदे गए, जबकि 72 चाहिए।

वायु रक्षा सिस्टम: आयरन डोम जैसे सिस्टम की कमी। मध्यम दूरी की मिसाइलें (MRSAM) और AWACS की भी कमी।

विशेषज्ञों की चेतावनी

2024: पूर्व एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने विमानों की कमी पर चिंता जताई।

2025: अमर प्रीत सिंह ने CII सम्मेलन में देरी और पारदर्शिता की कमी को उठाया।

नौसेना

युद्धपोत और पनडुब्बियां: 117 युद्धपोत और पनडुब्बियां, लेकिन माइन काउंटरमेजर वेसल्स (MCMV) की एक भी इकाई नहीं।

पनडुब्बियाँ: 24 की जरूरत है, केवल 16 उपलब्ध।

विमानवाहक पोत: INS विक्रांत कमीशन हुआ, लेकिन दूसरा पोत निर्माणाधीन।

विशेषज्ञों की चेतावनी

2023: कैप्टन (रि.) के.के. अग्निहोत्री ने पनडुब्बियों की कमी पर जोर दिया।

2025: रक्षा विशेषज्ञों ने MCMV की कमी को रणनीतिक कमजोरी बताया।

स्टेल्थ विमानों का ख़तरा

ऑपरेशन सिंदूर ने वायु सेना की अहमियत को रेखांकित किया। लेकिन एक नई चुनौती सामने है। सूत्रों के मुताबिक, चीन ने पाकिस्तान को पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ J-35A लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है। स्टेल्थ तकनीक रडार से बचने में सक्षम होती है, जो भारत के लिए खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हवाई शक्ति का संतुलन पाकिस्तान के पक्ष में हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने AMCA (पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान) के लिए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को मंजूरी दी है, लेकिन इसका प्रोटोटाइप 2028 तक और पूर्ण उत्पादन 2035 तक होगा। तब तक भारत के पास कोई पांचवीं पीढ़ी का विमान नहीं होगा, जिससे रणनीतिक कमजोरी बढ़ेगी।

रक्षा बजट

भारत का रक्षा बजट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है, लेकिन यह चुनौतियों के लिए अपर्याप्त है।

2024-25: 6.2 लाख करोड़ रुपये, जिसमें आधुनिकीकरण के लिए 1.72 लाख करोड़ (27%) जो जीडीपी का 1.9% है। यह चीन (2.1% जीडीपी) और पाकिस्तान (2.36% जीडीपी) से कम है।

मेक इन इंडिया: सरकार ने 65% रक्षा उपकरण स्वदेशी बनाने का दावा किया, लेकिन तेजस, धनुष तोप, और MCMV जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी बनी हुई है। 44,000 करोड़ रुपये की MCMV परियोजना को मंजूरी मिली, लेकिन पहला युद्धपोत 7-8 साल बाद तैयार होगा। वेतन और पेंशन पर 70% से ज्यादा खर्च होने से आधुनिकीकरण के लिए संसाधन सीमित हैं। संसद की स्थायी समिति (2018) ने सुझाव दिया कि रक्षा बजट को जीडीपी का 3% करना चाहिए।

सिंदूर और सियासत

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, बीजेपी और सरकार ने इसे 2025 के राज्य चुनावों में भुनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हर जोड़े को 1 लाख रुपये और सिंदूरदानी देने की घोषणा की। बीजेपी कार्यकर्ता "घर-घर सिंदूर" बांटने की योजना बना रहे हैं, इसे ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पल-पल की निगरानी की, लेकिन रक्षा खरीद और आधुनिकीकरण पर ऐसी निगरानी नहीं दिखती। उनके रोड शो, जैसे गुजरात के दाहोद (26 मई 2025) में, भारी भीड़ जुटाते हैं। वह "पाकिस्तान में घुसकर मारा" जैसे डायलॉग्स बोलते हैं, लेकिन सेना की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते।

सिंदूर की पुड़िया की जगह ऑपरेशन सिंदूर पर निबंध प्रतियोगिता की घोषणा

वरिष्ठ संवाददाता

रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर पर निबंध प्रतियोगिता की घोषणा की है, जो 1 से 30 जून तक चलेगी। विपक्ष के आरोपों के बीच कि सरकार राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ सैन्य हमले का इस्तेमाल कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शीर्ष तीन विजेताओं को प्रत्येक को 10,000 का नकद पुरस्कार मिलेगा और लाल किले में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने का एक विशेष अवसर मिलेगा।

रक्षा मंत्रालय ने रविवार को पोस्ट किया, "रक्षा मंत्रालय युवा दिमागों को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आमंत्रित करता है! #ऑपरेशन सिंदूर - आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को फिर से परिभाषित करना" विषय पर रक्षा मंत्रालय और @mygovindia द्विभाषी निबंध प्रतियोगिता में भाग लें।प्रतियोगिता की तिथियां: 1-30 जून 2025। प्रति व्यक्ति एक प्रविष्टि। हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुतियाँ स्वीकार की जाएँगी," प्रतियोगिता विवरण और ऑपरेशन सिंदूर लोगो प्रदर्शित करने वाले पोस्टर के साथ। बता दें कि भाजपा ने पहले कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का उपयोग करने की योजना बनाई थी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान प्रमुखता हासिल की। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर महिलाओं के बीच पार्टी की पहुंच के लिए। हालांकि, रविवार को जनता के आक्रोश और निंदा के बाद पार्टी ने इस तरह के आउटरीच कार्यक्रम की मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया। पिछले हफ्ते, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी पर पाकिस्तान पर भारत के सैन्य हमलों से राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि वह ऑपरेशन के नामकरण के साथ "राजनीतिक होली" खेल रहे थे, ऐसे समय में जब विपक्षी नेता ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के कूटनीतिक आउटरीच के हिस्से के रूप में विदेश में थे।

सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के प्रतिशोध में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी। लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और तोपखाने से जुड़ी लगभग चार दिनों की भीषण लड़ाई के बाद, भारत और पाकिस्तान ने 10 मई को जमीन, हवा और समुद्र पर सभी सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने के लिए "समझौता" किया।

बिहार चुनाव में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की एंट्री, 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

राजनीतिक डेस्क

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द की अगुवाई वाली पार्टी भी बिहार चुनाव में दस्तक देगी। इसकी घोषणा भी कर दी गई है। शंकराचार्य ने एक नयी पार्टी का गठन किया है। नाम रखा है गौ रक्षा दल। बिहार की सभी 243 सीटों पर यह पार्टी उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। शर्त केवल यही है कि इस पार्टी का उम्मीदवार वही बन सकता है जो गौ रक्षा का संकल्प लेगा और सनातन धर्म के प्रति उसका आस्था होगी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी के विद्या मठ में मीडिया से हुई बातचीत में ये बयान दिया कि जब वो गौ रक्षा के लिए कानून बनाने एवं गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से सम्पर्क किए तो उनको निराशा हुई क्योंकि किसी भी दल में इसके लिए निष्ठा नहीं दिखी। ऊपर से तो सभी ने हां कहा लेकिन किसी में इच्छाशक्ति नहीं दिखी। तभी हमने ये तय कर लिया कि जब सबकुछ राजनीति से ही तय होना है तो फिर गौ रक्षक दल भी चुनाव लड़ेगा। इसकी शुरुवात हम बिहार से कर रहे हैं। आगे जहां कहीं भी चुनाव होगा गौ रक्षा दल वहां चुनाव लड़ेगा। देश के सबसे बड़े वोटबैंक से जुड़ा है गाय का मुद्दा आज नही तो कल लोगों का समर्थन हमें जरूर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जो हमारे गोस्वामियों की परंपरा है, उस परंपरा का पोषण करना चाहिए। अगर वहां कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे आपस में बैठकर उस पर विचार करना चाहिए और उस गड़बड़ी को दूर करने पर विचार करना चाहिए। लेकिन व्यवस्था के नाम पर या कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसको दिखाकर अगर सरकार वहां पर प्रवेश करना चाह रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारा धर्म स्थान है वो अब धर्म निरपेक्ष स्थान होने जा रहा है। धर्म स्थान और धर्मनिरपेक्ष स्थान में बहुत अंतर है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं रह गया जब से धर्मनिरपेक्ष स्थान हो गया। आप अगर मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं तो पहले संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाएं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण से नाराज़ हैं। शंकराचार्य ने कहा, 'बातें अलग तरह की कही जा रही हैं और व्यवहार अलग तरह का हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सनातन को मानने वाले सरकार में हैं और दूसरी तरफ आप मंदिरों को छीन रहे हैं। हम तो वृंदावन के धर्माचार्यों से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो बांके बिहारी मंदिर का ट्रस्ट बनाकर एक तरीके से सरकारी अधिग्रहण किया जा रहा है, उसे मत होने दीजिए।

फिर डराने लगा कोरोना एक्टिव केस 4000 के पार

न्यूज़ डेस्क

देश में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 से पांच लोगों की मौत हो गई है जबकि सप्ताह भर के भीतर दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अभी तक सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4026 पहुंच गई है।और यह जिस तेजी से फ़ैल रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसका फैलाव कई राज्यों तक हो सकता है ,और बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से ज्यादा मौत की खबर मिल रही है।

महाराष्ट्र में चिंता की स्थिति

महाराष्ट्र की स्थिति सबसे नाजुक बताई जा रही है। राज्य में अब तक इस करीब हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 800 से ज्यादा अब भी सक्रिय मरीज हैं। केवल मुंबई में ही 20 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में 44 नए केस सामने आए, और राज्य में अब 331 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, जहां 87 नए मामलों के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 311 हो गई है।

24 घंटे में 5 लोगों की मौत

बीते दिन जिन मरीजों की मौत हुई, उनमें केरल के 80 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं जिन्हें निमोनिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी बीमारी थी। महाराष्ट्र में 70 और 73 साल की दो महिलाओं की जान गई, दोनों मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थीं। तमिलनाडु में 69 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई, जिन्हें टाइप-2 डायबिटीज और पार्किंसन रोग था। पश्चिम बंगाल में 43 वर्षीय महिला की मौत हुई, जिन्हें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक और किडनी फेल्योर की समस्या थी। इससे पहले दिल्ली में भी एक 60 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है, जो आंतों की बीमारी से पीड़ित थीं और बाद में कोविड से संक्रमित हो गई थीं।

संघ प्रमुख भागवत ने फिर अलापा हिन्दू राष्ट्र का राग

विशेष संवाददाता

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अभी बहस जारी ही है लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से हिन्दू राष्ट्र का राग अलापना शुरू कर दिया है। अब हिन्दू राष्ट्र की यह नयी कहानी ऑपरेशन सिंदूर को कितना प्रभावित करेगी यह देखने की बारी है। जब पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा है ऐसे में मोहन भगवत के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीते रविवार को कहा कि "हिंदू राष्ट्र" संघ का "शाश्वत विचार" है और हिंदू समाज से एकजुट होने और भारत को इतना मजबूत बनाने का आग्रह किया कि इसे कई शक्तियों के गठबंधन से भी हराया न जा सके। उनकी यह टिप्पणी आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक, ऑर्गनाइजर के साथ एक साक्षात्कार में आई, जिसमें उन्होंने "हमारी सभी सीमाओं पर बुरी ताकतों" की मौजूदगी को चिन्हित किया और कहा कि यही कारण है कि भारत के पास "शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है"। ऑर्गनाइजर ने कहा कि यह साक्षात्कार पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर से पहले आयोजित किया गया था।

भागवत ने "हिंदू राष्ट्र" के विचार पर जोर देते हुए कहा कि यह संघ के हर कार्य के पीछे "शाश्वत विचार" बना हुआ है।उन्होंने कहा, "संघ में नित्य (स्थायी) क्या है? बालासाहेब (देवरस, संघ के तीसरे प्रमुख) ने एक बार कहा था, 'हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है'।" "इसके अलावा, संघ में बाकी सब कुछ क्षणिक है। पूरा हिंदू समाज इस राष्ट्र का जवाबदेह संरक्षक है। इस देश की प्रकृति और संस्कृति हिंदू है। इसलिए, यह एक हिंदू राष्ट्र है।" पड़ोसी देशों बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और शोषण के विषय पर भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हिंदुओं की चिंता तभी होगी जब हिंदू काफी मजबूत होंगे।" "जब हिंदू समाज और भारत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हिंदू समाज का गौरवशाली स्वरूप भारत के लिए गौरव लाएगा। ऐसा मजबूत हिंदू समाज ही भारत के उन लोगों को साथ लेकर चलने का आदर्श प्रस्तुत कर सकता है जो खुद को हिंदू नहीं मानते, क्योंकि एक समय वे भी हिंदू थे। "अगर भारत का हिंदू समाज मजबूत होगा, तो अपने आप ही हिंदू विश्व स्तर पर मजबूत होंगे। यह काम चल रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है।"

भागवत ने कहा कि हिंदू "धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से" जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। "इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया गया है, वह अभूतपूर्व है। यहां तक कि स्थानीय हिंदू भी अब कह रहे हैं: 'हम भागेंगे नहीं। भागवत ने कहा, 'हम यहीं रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे।' भारत की सुरक्षा, सैन्य शक्ति

हिंदू "धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से" जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। "इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया गया है, वह अभूतपूर्व है। यहां तक कि स्थानीय हिंदू भी अब कह रहे हैं: 'हम भागेंगे नहीं।

और आर्थिक शक्ति के लिए संघ के दृष्टिकोण पर एक सवाल का जवाब देते हुए भागवत ने कहाः 'हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए।' 'कोई भी हमें जीतने में सक्षम नहीं होना चाहिए - भले ही कई शक्तियां एक साथ आ जाएं। दुनिया में ऐसी बुरी ताकतें हैं जो स्वभाव से आक्रामक हैं।' भागवत ने कहा कि भारत की शक्ति का स्वभाव 'अच्छे लोगों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए' होना चाहिए। 'जब कोई विकल्प उपलब्ध न हो, तो दुष्टता को बलपूर्वक मिटाना होगा।' भागवत ने एक बयान में ऑपरेशन सिंदूर के संचालन के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा था कि इसने 'देश के स्वाभिमान और मनोबल को बढ़ाया है।' यह भी हालांकि, वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर चुप रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता को समाप्त करने में मध्यस्थता की है। अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि संघ इस दावे से परेशान है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर कांग्रेस नेता का कबूलनामा

राजनीतिक डेस्क

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा के निशाने पर चढ़ी कांग्रेस सांसद गौरव गोगई की ब्रिटिश पत्नी के बारे में अभी हाल में ही कांग्रेस के ही पूर्व सांसद रिपुन बोरा का कबूलनामा असम की राजनीति को गर्म कर दिया है और बीजेपी के साथ ही सीएम सरमा के आरोप को बल दे दिया है। हालांकि यह भी सच है कि गोगोई की पत्नी के बारे में बीजेपी जो भी आरोप लगा रही है वह सब राजनीति से प्रेरित है लेकिन गोगोई की मुश्किलें तो बढ़ ही गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने "चौंकाने वाला कबूलनामा" किया है कि उनकी पार्टी के सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी "पाकिस्तान सरकार के पेरोल" पर थी। सरमा ने कहा कि उन्हें "इन विवरणों के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी" और कांग्रेस नेता रिपुन बोरा का बयान दर्ज किया जाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई से कथित संबंध को लेकर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने भारत और पाकिस्तान के बीच 19 बार यात्रा की थी। पूर्व राज्यसभा सांसद बोरा ने रविवार को कहा था कि कोलबर्न एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ में काम करती हैं, जिसका नेटवर्क पाकिस्तान और अन्य देशों में है। "इस संबंध में, उन्हें पाकिस्तान से वेतन मिला था और उन्होंने काम के लिए कई बार देश का दौरा किया था। लेकिन क्या यह किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाने का आधार हो सकता है? कई भारतीय और पाकिस्तानी एक-दूसरे के देशों में कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। "

सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, '' वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री रिपुन बोरा ने एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि माननीय सांसद श्री गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी वास्तव में पाकिस्तान सरकार के वेतन पर काम करती थी।" उन्होंने कहा कि यदि बोरा का बयान सच है, तो "यह राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में गंभीर रूप से चिंताजनक प्रश्न उठाता है"। सरमा ने कहा, "एक शत्रुतापूर्ण विदेशी राज्य से जुड़े व्यक्ति की "एक मौजूदा सांसद के अंदरूनी घेरे में" निरंतर उपस्थिति भारत की संस्थाओं की अखंडता के लिए एक गंभीर और अस्वीकार्य खतरा है।" उन्होंने कहा, "हमें पहले इन चौंकाने वाले विवरणों के बारे में पता नहीं था। अब जब यह खुलासा हुआ है, तो मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।" मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि

राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है और उन्होंने कहा, "हम बोरा का बयान दर्ज करेंगे और इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।" इससे पहले गोगोई ने सांसद के कथित पाकिस्तानी संबंधों के आरोप को लेकर सरमा की आलोचना की थी और घरेलू मोर्चे पर मुद्दों के कारण उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया था। उन्होंने यहां तक कहा कि सीएम की टिप्पणी "हास्यास्पद, निराधार, पागलपन और बकवास" थी और वह तथ्यों की जांच किए बिना "आईटी सेल ट्रोल" की तरह व्यवहार कर रहे थे।

बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष की पार्टी से बढ़ती दूरियां

मुझे एक जून को अमित जी के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा पार्टी के दिग्गजों के साथ देखे जाते हैं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो मैं अमित जी जैसे नेताओं के साथ उनके कार्यक्रमों में जाता था. अब मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करना पसंद करूंगा : घोष

राजनीतिक डेस्क

बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार दिलीप घोष पिछले महीने काफी चर्चा में रहे। चर्चा दो कारणों से हुई थी। पहला कारण तो यह था कि उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की थी और दूसरा कारण उनके विवाह को लेकर था। हालाँकि विवाह किसी भी इंसान का व्यक्तिगत मामला है लेकिन जब सक्से दिलीप घोष की मुलाकात ममता से हुई है, तभी से वे पार्टी के रडार पर हैं। न तो वे पार्टी की बैठकों में जा रहे हैं और न ही पार्ट्री उन्हें कहीं भी आमंत्रित कर रही है। लगता है कि दिलीप घोष पार्टी के लिए अछूत से हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष बीते रविवार को पार्टी की संगठनात्मक बैठक से दूर रहे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरी बार था जब पूर्व सांसद और भाजपा की बंगाल यूनिट के पूर्व अध्यक्ष किसी बड़े बीजेपी नेता के कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुए। इससे पहले 29 मई को उत्तरी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा में भी वह मौजूद नहीं थे। घोष ने पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

भाजपा के कई नेताओं ने उन पर टीएमसी प्रमुख बनर्जी से नजदीकी बढ़ाने और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। हालांकि, घोष ने कहा था कि उन्हें पूजा स्थल पर जाने का पूरा अधिकार है और कोई भी भाजपा के वफादार के रूप में उनकी ईमानदारी और साख पर सवाल नहीं उठा सकता। हालांकि, विवाद नहीं थमा और बाद में घोष को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, 'मुझे एक जून को अमित जी के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा पार्टी के दिग्गजों के साथ देखे जाते हैं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो मैं अमित जी जैसे नेताओं के साथ उनके कार्यक्रमों में जाता था. अब मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करना पसंद करूंगा। ' घोष ने 29 मई को मोदी की जनसभा से पहले भी इसी तरह कहा था कि उन्हें राज्य भाजपा नेतृत्व ने आमंत्रित नहीं किया है।

घोष पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ रविवार को अपनी ससुराल गए. वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे हर बैठक में आमंत्रित करना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि मुझे कुछ बैठकों में आमंत्रित किया जाए और कुछ में नहीं। पार्टी के प्रमुख कार्यक्रमों में घोष की अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने संवाददाताओं से कहा कि 'दिलीप दा एक वरिष्ठ नेता हैं। मैं वास्तव में उनकी अनुपस्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकता। दिलीप घोष आगे क्या कुछ करेंगे यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन बंगाल की राजनीति में जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक उनका सद्भाव अभी ममता बनर्जी के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। वे ममता के साथ जाते हैं या नहीं यह तो समय ही बताएगा लेकिन ममता बनर्जी चाहती है कि अगर दिलीप डा टीएमसी के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें ख़ुशी होगी। बंगाल में अगले साल ही चुनाव होने हैं।

240 भारतीय युवकों को कट्टरपंथी बनाने में नफीसा का हाथ

गजवा-ए-हिंद से अपने संबंध स्थापित करते हुए, तुफैल "2047 से पहले भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने और देश में शरीयत कानून लागू करने" से संबंधित सामग्री पोस्ट करता था।

न्यूज़ डेस्क

पाकिस्तान का भारत में जासूसी नेटवर्क कितना फ़ैल गया है इसकी जानकारी सामने आने के बाद बड़े स्तर पर जांच की जरुरत दिखने लगी है। पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी करने वालों में अभी तक दर्जन भर से ज्यादा लोग पकडे जा चुके है। इन पकडे गए आरोपियों में हिन्दू के साथ ही मुसलमान युवक और युवतियां भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी एटीएस ने एक समूह का भंडाफोड़ किया है ,वह चौंकाने वाला है। पाकिस्तान लिए जासूसी करने के आरोप में पिछले महीने के 21 मई को वाराणसी से उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा गिरफ्तार किए गए 34 वर्षीय तुफैल मकसूद के सभी संपर्क, 800 से अधिक व्यक्ति एजेंसी के रडार पर हैं। सभी 800 लोगों को तुफैल द्वारा संचालित 19 व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा गया था।

गौरतलब है कि यूपी एटीएस ने इसी सिलसिले में 21 मई को वाराणसी से तुफैल मकसूद, 45 वर्षीय दिल्ली निवासी मोहम्मद हारुन को नोएडा से और 18 मई को इसी सिलसिले में रामपुर निवासी 35 वर्षीय शहजाद वहाब को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था। तीनों फिलहाल पूछताछ के लिए एटीएस की हिरासत में हैं। तुफैल के फोन से सभी 800 संपर्कों का ब्योरा हासिल किया गया। एटीएस के एक सूत्र ने दावा किया कि तुफैल वाराणसी, जौनपुर, मऊ, भदोही, मिर्जापुर,

प्रतिकात्मक

चंदौली और गाजीपुर समेत पूर्वी यूपी के सात जिलों में अपने मॉड्यूल के संपर्क में रहने के लिए 19 व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था।

वह कथित तौर पर सीमा पार से मौलवियों और आतंकी समूह के 'नेताओं' के भड़काऊ भाषण पोस्ट करके पाकिस्तान धर्म के नाम पर उन्हें कट्टरपंथी बनाने में शामिल था। गजवा-ए-हिंद से अपने संबंध स्थापित करते हुए, तुफैल "2047 से पहले भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने और देश में शरीयत कानून लागू करने" से संबंधित सामग्री पोस्ट करता था। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा, उसे ऐसी सामग्री एक पाकिस्तानी महिला नफीसा द्वारा भेजी जा रही थी, जिसके साथ वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिछले चार महीनों से संपर्क में था।

नफीसा के सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चला है कि वह 240 भारतीय युवकों के संपर्क में थी, जिनमें से छह बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, कन्नौज, लखनऊ और वाराणसी के थे। एक सूत्र ने कहा, "संदेह है कि आईएसआई नफीसा का इस्तेमाल भारतीय युवकों से जुड़ने और उन्हें जासूसी गिरोह और अन्य नापाक गतिविधियों में शामिल करने के लिए कट्टरपंथी बनाने के लिए कर रही थी।"

नफीसा ने भारतीय युवाओं का एक नेटवर्क बनाया था और धर्म के नाम पर मुस्लिम युवकों को भड़काकर नफरत फैला रही थी और देश में अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार कर रही थी। तुफैल भारत में सक्रिय उसके नेटवर्क के सदस्यों में से एक था। इससे पहले एटीएस ने दावा किया था कि वाराणसी के जैतपुरा निवासी तुफैल मकसूद कम से कम 600 पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों के संपर्क में था और भारत की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करता था। एजेंसी ने कहा कि तुफैल अत्यधिक कट्टरपंथी है, क्योंकि वह प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो और "बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला" लेने से संबंधित सामग्री साझा करता था।

पीपल रिसर्च की रिपोर्ट

52% किसानों की आय के स्रोत खेती नहीं

न्यूज़ डेस्क

अन्नदाता परिवारों और खेती से परे उनकी आजीविका की पुनर्कल्पना' शीर्षक से प्रकाशित पेपर से पता चलता है कि 52% कृषि परिवार अब गैर-कृषि गतिविधियों से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव और पर्यावरण से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण खेती में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से अन्नदाता गैर-कृषि क्षेत्र से आमदनी के स्रोतों की ओर रुख कर रहे हैं। पेपर में कहा गया है, 'विविधीकरण की ओर यह रुझान उन्हें अधिक फाइनेंशियल लचीलापन प्रदान करता है। यह कृषि आय से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो कि कीमत में अस्थिरता, मौसम की घटनाओं और अन्य बाहरी आर्थिक झटकों की वजह से अत्यधिक अस्थिर हो सकती है।'

गैर कृषि गतिविधियों से आमदनी करने वाले कृषक परिवारों में सबसे ऊपर नगालैंड है, जहां 98 प्रतिशत किसान गैर कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। इसके बाद त्रिपुरा (94 प्रतिशत), मेघालय (85 प्रतिशत), तमिलनाडु (83 प्रतिशत), सिक्किम और उत्तराखंड (80 प्रतिशत) का स्थान है। बहरहाल अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अभी भी 82 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उनकी आमदनी का एकमात्र स्रोत कृषि है। इसके बाद पंजाब (78 प्रतिशत), असम (77 प्रतिशत), कर्नाटक और मणिपुर (73 प्रतिशत) का स्थान है। इससे पता चलता है कि कृषि से जुड़े परिवारों ने 2024-25 में सालाना 7,31,000 रुपये कमाए हैं। हालांकि इस आंकड़े में बहुत उतार-चढ़ाव है। गरीब किसान परिवारों की औसत सालाना आमदनी 2,03,000 रुपये है, जबकि अमीर किसान परिवारों की औसत सालाना आमदनी 26 लाख रुपये है। बहरहाल अगर कृषि से जुड़े परिवारों की आमदनी में हिस्सेदारी की बात करें तो अभी भी उनके कुल आय की करीब 80 प्रतिशत कमाई कृषि गतिविधियों से हो रही है, जिसमें 67.1 प्रतिशत सीधे कृषि गतिविधियों से कमाई शामिल है। कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे डेरी और पशुपालन की कुल कमाई में हिस्सेदारी 7.4 प्रतिशत और कृषि श्रम की हिस्सेदारी 4.4 प्रतिशत है।

दिल्ली का चिड़ियाघर अंबानी के हवाले

न्यूज़ डेस्क

दिल्ली का चर्चित चिड़ियाघर अब अंबानी के पास चला गया है। सरकार ने ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आयी है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि चिड़ियाघर को और आधुनिक किया जाएगा अजर दर्शकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएँगी। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार के पास देश के इस चिड़ियाघर को भी चलाने के लिए पैसे नहीं हैं ? क्या सरकार इसे आधुनिक नहीं बना सकती है ? लेकिन यह सवाल सरकार से पूछे कौन ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि समझोते के दस्तावेज पर दस्तखत हो गए और चिड़ियाघर के निदेशक को इसकी जानकारी तक नहीं है। यह समझोता Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre, जामनगर अर्थात अंबानी पुत्र के वनतारा से हुआ है जो की दिल्ली चिड़ियाघर का प्रबंधन देखेगा। उनकी एक टीम यहां आ कर सब कुछ सर्वे भी कर गई।

बता दें कि वनतारा जामनगर, गुजरात में स्थित एक अत्याधुनिक वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र के नाम पर अनंत अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से रिलायंस रिफाइनरी के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगभग 3000 एकड़ (कुछ स्रोतों के अनुसार 3500 एकड़) में फैला हुआ है। भारत में 1972 का वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट लागू है, जो जंगली जानवरों के शिकार, व्यापार, आयात-निर्यात और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए सख्त प्रावधान करता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था को जंगली जानवरों को पकड़ना, रखना, या उनका व्यापार करना बिना सरकारी अनुमति के प्रतिबंधित है। मई 2024 में वेनेजुएला से 1,825 जीवित जानवरों को एक प्राइवेट समझौते के तहत भारत लाया गया, जिनमें जैगुआर, टापिर, मगरमच्छ, बंदर आदि शामिल थे। यह सौदा कथित तौर पर 'संरक्षण' के नाम पर हुआ, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी और सरकारी निगरानी की अनदेखी के आरोप लगे हैं। भारत में जू अथवा रेस्क्यू सेंटर खोलने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन वनतारा की प्रक्रिया में कई नियमों की अनदेखी की बात सामने आई ।

आपातकाल को कुरेदने के लिए संसद का विशेष सत्र

वरिष्ठ संवाददाता

वैसे तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां पहलगाम हमले के बाद से ही सरकार को कह रही है कि वह संसद का विशेष सत्र बुलाये ताकि सब कुछ साफ़ हो सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार को पता है कि संसद सत्र में इस मसले पर कई सवाल खड़े होंगे जिससे बीजेपी समेत सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी। सामने बिहार का चुनाव है और सरकार ऐसा कोई भी परेशानी झेलने को तैयार नहीं है। इधर खबर मिल रही है कि सरकार विपक्ष की मांग को दरकिनार करते हुए अपने हिसाब से संसद का विशेष सत्र इसी महीने के आखिरी सप्ताह में बुलाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक़ यह सत्र 25 -26 जून को हो सकता है। लेकिन यह सत्र पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं बल्कि 50 साल पहले देश में आपातकाल के दौरान क्या हुआ ,इस पर संसद का विशेष सत्र चलाया जाएगा।जाहिर है मोदी सरकार बिहार चुनाव को देखते हुए संसद का यह विशेष सत्र बुला रही है ताकि आपातकाल की यादों को ताजा किया जा सके और बिहार चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके।

राजनीतिक मकसद से विशेष सत्र

कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार की इस बात को लेकर आलोचना की है कि पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग को अनदेखा कर सरकार अब खास सियासी मकसद से संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है।कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि सियासी मकसद से 25-26 जून को संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश ने पोस्ट में कहा कि, ''22 अप्रैल की रात से ही कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमलों और उसके बाद के हालात को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही है। यह बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है।''

उन्होंने पोस्ट में आगे कहा कि 10 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष-दोनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था, ताकि पहलगाम आतंकी हमलों और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर चर्चा की जा सके और एक साझा प्रस्ताव के माध्यम से सामूहिक संकल्प प्रकट किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया है। जयराम रमेश ने पोस्ट में कहा कि, ''अब सुनने को मिल रहा है कि 25-26 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि, ''यह प्रधानमंत्री द्वारा वास्तविक और अधिक तात्कालिक मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक और अनोखा उदाहरण होगा,

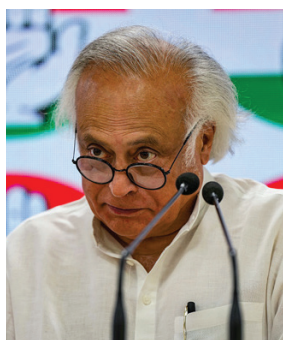

<u>सीडीएस के खुलासे के बाद कांग्रेस ने तत्काल संसद का विशेर्ष सत्र बुलाने की मांग सरकार से की है। सीडीएस जनरल चौहान ने बीते शनिवार को सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक साक्षात्कार में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के शुरुआती नुकसान की बात कही है।</u>

जबकि उन्हीं के नेतृत्व में देश पिछले 11 वर्षों से एक अघोषित आपातकाल की स्थिति में है।'' रमेश ने दावा किया प्रधानमंत्री इन सवालों से लगातार बचते रहे हैं कि पहलगाम हमले के लिये जिम्मेदार आतंकी अब तक फरार क्यों हैं, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संघर्षविराम के लिए मध्यस्थ बनने की अनुमति क्यों दी और 19 जून, 2020 को सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट क्यों दी? बाद में, रमेश ने कहा कि वर्तमान मुद्दों और चुनौतियों के बारे में बात करने के बजाय सत्तापक्ष इस बात पर चर्चा करना चाहता है कि 50 साल पहले क्या हुआ था। उन्होंने यह मांग भी दोहराई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और भारत एवं पाकिस्तान से जुड़ी नई चुनौतियां, विशेषकर दोनों के बीच की ''जुगलबंदी'' के मद्देनजर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर पारित फरवरी, 1994 के उस प्रस्ताव को दोहराया जाए और उसे आज की परिस्थितियों के मुताबिक बनाया जाए। उस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है।

आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया ?

रमेश ने यह सवाल भी किया कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? रमेश ने कहा, ''जब पाकिस्तान और आतंकवादियों को निशाना बनाना चाहिए, तब भाजपा को केवल कांग्रेस को निशाना बनाने और उस पर हमला करने में दिलचस्पी है।'' कांग्रेस हाल के दिनों में कई बार यह मांग कर चुकी है कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा किए जा रहे इस दावे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी "चुप्पी" तोड़नी चाहिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष व्यापार एवं शुल्क को आधार बनाकर रुकवाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया है।

आजाद भारत बदलाव के तीन दशक (1948- 1977) (भाग तीन)

योजनागत वि
बैंकिंग और अन्य

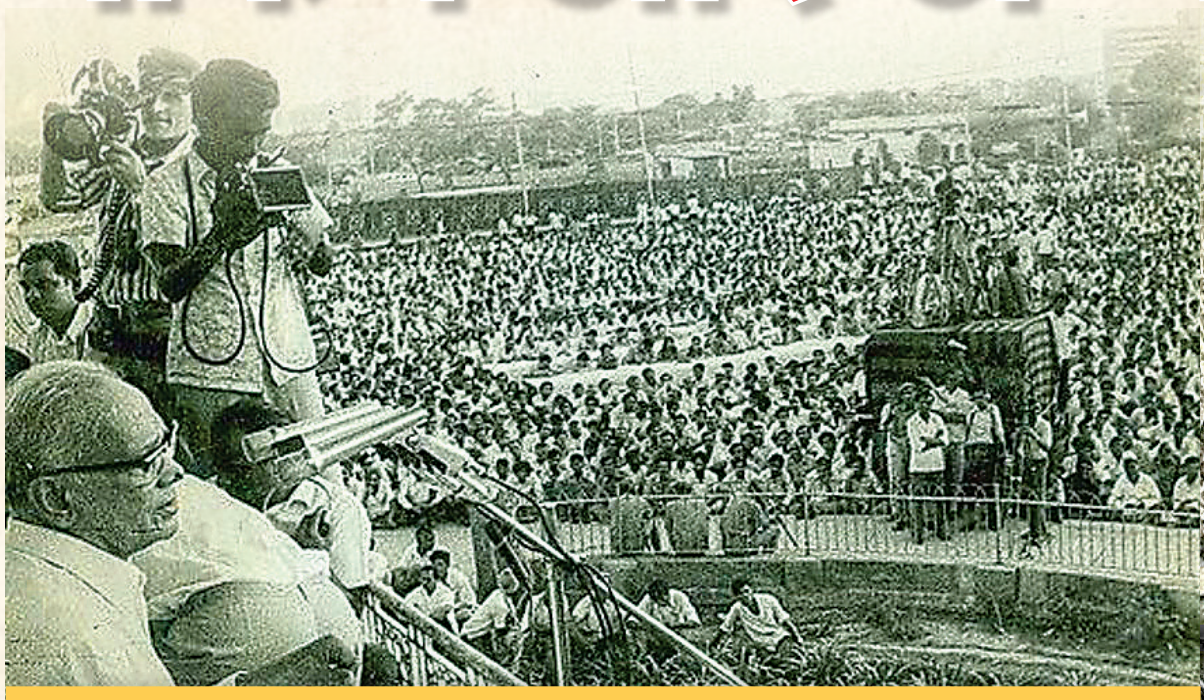

आजादी के बाद देश में कई तरह के बदलाव होने लगे थे। यह बात और है कि आजादी के समय भारत एक गरीब देश तो था ही सामाजिक और आर्थिक असमानता भी काफी गहरी थी। देश में दो ही वर्ग थे। या तो समाज का एक तपका धनी या फिर जमींदार समाज से आता था ,तो दूसरा तपका गरीबों का था। देश की बड़ी आबादी गरीबो की ही थी। तब मध्यमवर्ग का कोई चलन नहीं था। लेकिन आजादी के बाद की सरकार की पहली प्राथमिकता तो यही थी कि आजाद भारत को गरीबी से मुक्ति कैसे मिले ? इसी गरीबी मुक्ति की चाह में सरकार ने कई बड़ी योजनाओं चलाई

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

देश आजाद हुआ , देश का अपना संविधान बना और लागू भी हुआ , आजाद भारत में प्रांतीय और केंद्रीय विधायी निकायों यानी राज्यों के विधानमंडल और संसद के चुनाव कराये जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ , देश के विकास के नए आदर्श भी स्थापित किये गए। ऐसे बहुत सारे काम हुए जो पहले देखने को नहीं मिलते थे। आम जान के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ शाही यानी इम्पीरियल था। यही वजह है कि हम गुलाम थे इस देश की जनता गुलाम थी । गुलाम भारत में रेल भी इम्पीरियल और नगरपालिखा जैसा स्थानीय निकाय भी इम्पीरियल होने से काम नहीं था। गुलाम भारत में सड़कें भी इम्पीरियल थी और बैंक भी इम्पीरियल ही थे। अच्छे स्कूल कॉलेज अस्पताल और अच्छे सार्वजनिक स्थल जहां मोटी रकम देकर जनसेवा की सुविधाएँ उपलब्ध थी वो नाम से न सही पर मिजाज से शाही यानी इम्पीरियल थे। इन स्थानों का उपयोग अंगरेजी सर्कार के टुकड़ों पर पल रहे कुछ धन्नासेठ और चाटुकार भारतीय राजनीतिज्ञ ही कर पा रहे थे। आजादी के बाद ये स्थितियां तेजी से बदलने लगी थीं जो कुछ शाही यानी इम्पीरियल था वो धीरे - धीरे आम होने लगा गया था।मसलन इम्पीरियल रेल भारतीय रेल हो गई और दिल्ली के स्थानीय निकाय इम्पीरियल बोर्ड को नईदिल्ली नगरपालिका का नया नाम भी मिल गया था। इसी कड़ी में देश का अपना संविधान लागू होने के ठीक एक साल पहले जनवरी 1949 एक बड़ा काम यह भी हुआ कि मसलन इम्पीरियल रेलवे भारतीय रेल हो गयी थी। दिल्ली में इम्पीरियल बोर्ड की जगह नईदिल्ली नगरपालिका बन गयी थी। इसी बीच देश का अपना संविधान लागू होने के ठीक एक साल पहले जनवरी 1949में देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और इम्पीरियल बैंक का नाम बदल कर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया कर दिया गया था।

प्रसंगवश आजाद भारत के दो प्रधानमंत्रियों - जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गाँधी का का उल्लेख करना तर्क सांगत लगता है जिनके बारे में यह धारणा चलन में है किये दोनों ही कहीं न कहीं साम्यवाद की विचारधारा से गहरे प्रभावित रहे हैं। नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री काल में किये गए कुछ कार्यों से उनके साम्यवादियों के करीब होने की पुष्टि भी होती है। देश की आजादी के डेढ़ साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का राष्ट्रीयकरण ऐसी ही एक घटना कही जा सकती है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन सोवियत संघ के वरिष्ठ साम्यवादी नेता स्टालिन से प्रभावित हो कर भारत में पांच वर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी की थी। कुछ इसी अंदाज में इंदिरा गाँधी ने भी अपने प्रधानमंत्री काल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण , गरीबी हटाओ और राजाओं के प्रीवीपर्स समाप्त करने जैसे काम किये थे।

योजना आयोग का गठन

प्रसंगवश, एक गौरतलब तथ्य यह भी है कि स्टालिन ने 1928 में ही सोवियत संघ में पांच वर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। राजनीतिक रूप से नेहरू उन्हें अपना आदर्श मानते थे इसलिए उन्होंने 22 साल बाद 1950 से भारत में भी पांच वर्षीय योजनाओं के इस सिलसिले की शुरूआत कर दी थी यही वो समय था जब आजाद भारत में विकास कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और उनको गति देने की शुरुआत हुई थी। इस काम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने की गरज से भारत में एक योजना आयोग का गठन भी इसी साल किया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद ही इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे . गुलजारीलाल नंदा को देश के योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। श्री नंदा देश के एक ऐसे राजनीतिज्ञ भी थे जिन्हें दो बार 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और 1966 में लालबहादुर शास्त्री के निधन के बाद भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का मौका तो जरूर मिला लेकिन वो पूर्ण प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सके थे . बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में योजना आयोग नाम के इस सरकारी संस्थान का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया था। योजना आयोग का गठन तो साल 1950 में हो गया था लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया इसके अगले साल 1951 से शुरू हुई थी।इसी साल पंचवर्षीय योजनाओं पर जमीन में काम शुरू करने के साथ ही एक बड़ा काम रेलवे के राष्ट्रीयकरण का भी हुआ था। इसके बाद को तीन रेलवे जोन में बांटा गया था। रेल की रफ़्तार बढ़ने और इसके विस्तार से देश की विकास याता को भी गति मिली। रेलवे आज भारत की जीवन रेखा बन चुकी है। दुनियाका सबसे बड़ा रेल नेटवर्क समझी जाने वाली भारतीय रेलवे की करीब डेढ़ लाख किलोमीटर लम्बी पटरियों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है और देश के करीब साढ़े सात हजार स्टेशन के माध्यम के रेलवे का कार्य संचालित होता है।

भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश / क्षेत्र

देश की आजादी के करीब ढाई साल बाद 1950 में विशेष राज्य का दर्जा देकर जम्मू कश्मीर राज्य के दो तिहाई हिस्से को भारत में और एक तिहाई हिस्से को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। इसके साथ ही तमाम तरह की दूसरी समस्याएं भी आजाद भारत के भारतीय शासकों के सामने आने लगी थीं। 1953 से देश में नए राज्यों के गठन की मांगे भी उठने लगी थी। राज्यों के सम्बन्ध में एक समस्या भारत के कई छोटे राज्यों और देशी रियासतों के भारत में विलीनीकरण , राष्ट्रीयकरण और नामकरण की भी थी। आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के पुनर्गठन को लेकर इस दौर में की जाने वाली मांगे कई बार उग्र भी हो जाती थीं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करने की मांग के केंद्र में थे गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामलू। गाँधी जी ने भी यह आश्वासन देश की आजादी से पहले दे रखा की देश के आजाद होने के बाद नेहरू देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस मांग को स्वीकार कर अलग राज्य का गठन

कांग्रेस की हार ,जनता पार्टी की सरकार

1977 में भारत की छठी लोकसभा के लिए हुए चुनाव में पहली बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और देश में विपक्ष की पहली सरकार बनी थी। जनता पार्टी की यह सरकार कांग्रेस छोड़ कर गए जनता पार्टी नेता मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठित हुई थी। अपने अंतर्विरोधों के चलते विपक्ष की यह सरकार अधिक समय तक नहीं टिकी नहीं रह सकी थी। श्री देसाई केबाद कुछ महीनों के लिए चौधरी चरण सिंह भी जनता सरकार के प्रधानमंत्री बने जरूर लेकिन बाद में 1980 में प्रचंड बहुमत से सरकार में वापसी कर इंदिरा गाँधी ने तत्कालीन गैर कोंग्रेसी विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया था। 1977 की इस घटना से एक दशक पहले 1967 के आसपास भी गैर कोंग्रेसवाद के नाम पर एकजुट हुए तात्कालीन विपक्षी दलों भारतीय जनसंघ , भारतीय लोकदल , पीएसपी , एस एस पी , स्वतंत्र पार्टी और काफी हद तक देश की वामपंथी पार्टियों ने भी कांग्रेस चुनाव में हारने के लिए एकजुटता दिखाई थी। इसका परिणाम इस रूप में देखने को भी मिला था कि उत्तर भारत के कई राज्यों में ख़ास तौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों संयुक्त विधायक दल की सरकारें बन गयी थीं। ये सिलसिला भी बहुत अधिक समय तक बना नहीं रह सका था। 1969 तक संयुक्त विधायक दलों का टूटना शुरू हो गया था और 1971 के आते - आते पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध और बांगला देश के रूप में एक नए राष्ट्र का गठन होने की घटना ने भारत के विपक्ष को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया थाऔर इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत होने का एक मौका और मिल गया था।

1952 में 38 चरणों में कराए गए लोकसभा के पहले वहुनाव में चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि 50 करोड़ की आबादी वाले इस देश की 85 फीसदी निरक्षर जनता को वोट देने के लिए लैस कैसे किया जाए। समस्या के समाधान के रूप में मतदानपत्र में उम्मीदवार का नाम छपने के साथ ही उस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी प्रकाशित करने का फैसला लिया गया जिस पार्टी का वो उम्मीदवार था। बैलेट पेपर के जरिए वोट देने की यही परंपरा आजादी का आठ दशक बाद आज भी वैसे ही जारी है। उस समय चुनाव आयोग ने देश की सभी पार्टियों को अलग - अलग चुनाव चिन्ह आबंटित किये थे। तब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी। कांग्रेस के पास यह चुनाव चिन्ह 1969 में हुए उसके पहले विभाजन तक रहा था।

उसके बाद इंदिरा गाँधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को आयोग ने गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा और बाद में इंसानी पंजा चुनाव चिन्ह के रूप में आबंटित किया था। पार्टी में विभाजन के बाद अलग अलग नाम से वजूद में आईं अन्य कांग्रेस पार्टियों को भी चुनाव आयोग ने पार्टी की पहचान के तौर पर अलग - अलग चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए थे। देश के पहले लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 1952 को संपन्न हुई थी। इसके 15दिन बाद 1 मई 1952 को पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की बैठक आयोजित की गयी थी। गणेश वासुदेव मावलंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।

चुनाव आयोग का गठन

भारत की विकास योजनाओं को गति देने के के समानांतर ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनाव प्रबंध के साथ लामबंद करने के गरज से भारत में चुनाव आयोग का गठन भी 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया था।सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनके नेतृत्व में दो साल बाद 1952 में पहली बार आजाद भारत के प्रादेशिक और केंद्रीय विधायी निकायों - विधान मंडलों और संसद के चुनाव कराये गए थे। चुनाव की यह प्रक्रिया कई दिनों चली थी और जनवरी 1952 में लोकसभा के और उसके बाद 216 सदस्यों वाले भारतीय सदन के उच्च सदन राज्य सभा के चुनाव कराए गए थे। उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आजाद भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति बने थे , भारत के संविधान में यही प्रावधान है कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है। पहली लोकसभा के चुनाव में आशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी को ही बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला था। पंडित नेहरू देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो सीधे जनता के वोट से चुनाव जीत कर संसद का सदस्य बने थे.. लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत का यह सिलसिला 1971 में पांचवीं लोकसभा के चुनाव तक बदस्तूर जारी रहा था और 1952 से लेकर 1962 तक संपन्न चुनाव में जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकारों का गठन हुआ था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गाँधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता की हैसियत से देश की प्रधानमंत्री बनी थी। गुलजारीलाल नंदा नेहरू और शास्त्री ने निधन के बाद दो अलग - अलग मौकों पर इनके उत्तराधिकारी के रूप में बहुत ही कम समय के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री बनाये गए थे।

विकास आकर्षण

विकसित भारत विविध सोपान

देश की आजादी के बाद विकास के विविध सोपानों पर एक क्रम से सुनियोजित तरीके से काम शुरू हुआ था। विधायी निकायों के चुनाव , पांच वर्षीय योजनाओं की शुरुआत , राज्यों का नए सिरे से पुनर्गठन राष्ट्रीयकरण और वर्गीकरण करने के बाद वैश्विक स्तर पर संबंधों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी थी जिसके खट्टे मीठे अनुभव भी मिलने शुरू हो गए थे। इस क्रम में 1954 के आस पास एक दौर ऐसा भी आया था जब भारत और चीन के आपसी सम्बन्ध काफी मजबूत होने लगे थे। भारत और चीन दोनों ही देश एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि दिल्ली और बीजिंग दोनों ही जगह हिंदी - चीनी भाई - भाई के नारे बड़े जोर शोर से लगने लगे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत का पालन करते हुए इन संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिशें भी की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि इसी बीच तिब्बत का संकट खड़ा हो गया। चीन ने तिब्बत के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिए थे और तिब्बती भाग कर भारत में शरण लेने लग गए थे। तिब्बत के लोगों का यहाँ आना और भारत का मानवता के नाते उनकी मदद करना , उन्हें शरण देना चीन को रास नहीं आया। इस वजह से भारत - चीन की दोस्ती दुश्मनी में बदल गयी थी। चीन के साथ हुई दोस्ती के दौर में पंचशील का समझौता इसलिए हुआ था कि इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच तिब्बत के माध्यम से आपसी व्यापार करने में सहूलियत हो लेकिन जब तिब्बत ही चीन के दुर्व्यवहार का शिकारहो रहा तब इस दोस्ती के आगे बढ़ने की सम्भावना भी धीरे ख़त्म होने लगी थी। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के साथ ही बड़ी तादाद में तिब्बत के लोगों को शरण देने से चीन भारत से इतना नाराज हो गया था कि 1962 में उसने भारत पर आक्रमण ही कर दिया था। इस युद्ध के लिए भारत तैयार नहीं था , इसका परिणाम यह हुआ की भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था और उसके कई हिस्सों पर चीन ने कब्जा कर लिया था।भारत और चीन के बीच हुए पंचशील के समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके चीनी समकक्ष चाउ एन लाईने हस्ताक्षर किये थे। चीन के युद्ध में मिली हार का सदमा जवाहरलाल नेहरू अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सके थे . इस सदमे के चलते 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया था। उनके स्थानापन्न के रूप में अल्प समय अवधि के लिए गुलजारी लाल नाडा देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। देश की आजादी के 8 साल बाद ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी कुछ लोगों को सम्मानित किया गया था। इन लोगों में देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी , वैज्ञानिक सीवी रमन,और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम विशेष रूप उल्लेखनीय हैं। यहां एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि भारत में व्यावसायिक कार्यों के लिए अंग्रेजी शासन में इम्पीरियल बैंक के नाम से जो संस्थान खोला गया था उसका भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नामकरण और राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को कर दिया गया था और इस सरकारी बैंक ने उस तारीख से अपना काम करना भी शुरू कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंधों की बात करें तो 7 जून 1955 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सोवियत संघ दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भारत के किसी प्रधानमंत्री का यह संभवत पहला सोवियत दौरा था। इस दौरे की एक खासियत इस रूप में भी देखी गयी कि इस मौके पर सोवियत संघ में कई जगहों पर पंडित नेहरू का उनके प्रिय फूल गुलाब से स्वागत किया गया था। नेहरू को गुलाब का फूल इतना प्रिय था कि उनकी अचकन पर गुलाब का एक फूल हमेशा लगा रहता था। गुलाब का यह फूल एक तरह से उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया था। नेहरू के इस दौरे को वैश्विक स्तर पर आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नेहरू यूरोप भी गए थे। 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन , निर्माण और राष्ट्रीयकरण का जो सिलसिला शुरू किया गया था वो 1956 और उसके बाद तक काफी समय तक चलता रहा था। राज्यों के पुनर्गठन का यह सिलसिला किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण करने के उद्देश्य से 1953 में बनाये गए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही साल 1956 में भारत में मध्य प्रदेश ,केरल , आंध्र प्रदेश , कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों का गठन किया गया था। भाषा के इसी फार्मूले को अपनाते हुए बाद के दौर में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल समेत कई राज्यों का निर्माण किया गया था। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण इसी लेख में एक जगह देखा जा सकता है। प्रसंगवश राज्यों / केंद्र शासित क्षेत्रो / प्रदेशों के सम्बन्ध में एक तथ्य यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इतना सब कुछ होते हुए भी देश के दिल्ली ,पुडुचेरी,अंडमान और निकोबार , लक्ष्य द्वीप जैसे कई ऐसे क्षेत्र थे जिन पर भारत की सरकार का नियंत्रण नहीं था , ऐसे तमाम क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेते हुए भारत सरकार ने इन्हें केंद्र शासित क्षेत्र / प्रदेश का दर्जा भी दिया। 1957 में भारत की दूसरी लोकसभा के लिए चुनाव कराया गे था। इसमें भी जीत कांग्रेस पार्टी की ही हुई थी। नेहरू एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने थे। इस चुनाव के बाद सरकार के कामकाज और तौर तरीकों में एक बदलाव इस रूप में भी देखने को मिला कि भारत की सरकार ने ब्रिटिश सरकार के जमाने से चले आ रहे सिक्कों में कई तरह के बदलाव किये और बाद में ये सिक्के बंद कर चलन से बाहर ही कर दिए गए थे। ऐसा ही एक सिक्का आने का था। उस समय 16 आने का एक रुपया हुआ करता था। एक रुपये में चार चवन्नी और दो अठन्नी होती थी। 1957 में एक राजनीतिक करिश्मा इस देश में यह भी हुआ था कि केरल विधानसभा के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी और उसने सरकार बनाई थी। किसी विपक्षी दल, उसमें भी किसी कम्युनिस्ट पार्टी की देश में बनाने वाली यह पहली सरकार थी। वरिष्ठ वामपंथी नेता ई एम एस नम्बूदरीपाद केरल की कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री बनाये गए थे 1957 तक गोवा सरीखे कई राज्य भारत सरकार का हिस्सा नहीं थे यहां पुर्तगालियों की सरकार वजूद में हुआ करती थी। इन राज्यों की सरकारों के सिपाही अक्सर ही सीमा शुल्क की आड़ में भारतीय सैनिकों से भिड़ जाया करते थे । अंततः तत्कालीन गृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल की सख्ती के चलते गोवा का भारत में विलय हुआ और इस समस्या से निजात मिली थी ।

भारतीय सेना का आधुनिकीकरण

1957 के बाद भारत अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरणके काम में लग गया था। इसी दौर में भारत को अपना पहला जेट बॉम्बर केनबरा विमान मिला था। युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए मशहूर इस विमान के मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गयी थी। इससे पाकिस्तान समेत कई दुश्मन देश सकते में आ गए थे। इसके कुछ समय बाद 1958 में यह खुशनुमा संयोग भी देखने को मिला था कि भारत एक तरफ अपनी सैन्य क्षमता में वृद्धि कर रहा था तो दूसरी तरफ खेल , कला , साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी उसकी अलग पहचान बनने लगी थी। इसी के परिणाम स्वरूप भारत के धावक फ्लाइंग किंग मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था और भारत की फिल्म मदर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था।इसी दौर में आजाद देश में आर्थिक घपलों की शुरुआत भी हो चुकी थी। हरिदास मूंगड़ा के नाम से मशहूर इस घोटाले में मुख्य आरोप यह था कि एल आई सी के सरकारी कर्मचारियों के साथ सांठ - गाठ कर एक करोड़ 24 लाख रुपये की हेरा फेरी की गयी थी और यह रकम मूंदड़ा की आधा दर्जन कंपनियों में खर्च की गयी थी। उस समय के हिसाब से करीब सवा करोड़ की यह रकम काफी बड़ी धनराशि मानी जाती थी और इसे एक बड़ा आर्थिक घोटाला माना गया था। इस घोटाले खबर लगने पर उस समय कांग्रेस के रायबरेली के सांसद फिरोज गाँधी ने संसद में अपने ही ससुर जवाहरलाल नेहरू को कटघड़े में खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री नेहरू मामले को ज्यादा हवा न देकर चुपचाप निपटा देना चाहते थे लेकिन फिरोज गाँधी ने ऐसा नहीं होने दिया , यह घोटाला ससुर - दामाद के बीच मनमुटाव का कारण भी बना और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एमसी छागला की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमीशन का गठन भी कर दिया गया था। इस कमीशन की जांच में नेहरू सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी कृष्णमाचारी को दोषी पाया गया था। इसी आरोप में उनको मंत्री पद से इस्तीफ़ा भी देना पद गया था। इस घटना ने नेहरू की साफ़ और ईमानदार राजनीतिज्ञ की छवि को भी दागदार बना दिया था। उधर चीन के साथ सम्बन्ध खराब होने की जिस घटना का हम पहले जिक्र कर चुके हैं , उस सम्बन्ध में इसी दौर में 1959के दौरान यह जानकारी भी मिलने लगी थी कि 31 मार्च 1959 की एक घटना से भारत चीन के सम्बन्ध ठीक नहीं खराब ही होंगे। यह घटना तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के भारत में शरण लेने से सम्बंधित थी चीन की नाराजगी की वजह से चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण ही कर दिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार से दो साल पहले साल 1960 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध मजबूत बनाने की भी एक कोशिश की थी। इसी कोशिश के तहत सिंधु जल समझौता हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने की दृष्टि से यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस समझौते के प्रावधानों को लेकर अमेरिका भी पूरी तरह संतुष्ट था। इस समझौते की प्रमुख महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक अमेरिकी विशेषज्ञ और टेनसी भारत और पाकिस्तान कीच वेल्ली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख ने भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के विवाद को तकनीकी रूप से हल करने का सुझाव इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से बहुत पहले दिया था। संयोग इस अमेरिकी विशेषज्ञ के सुझाव इस समझौते में शामिल थे। ये अमेरिकी विशेषज्ञ थे लिलीमेंथियल . गौरतलब है कि साल 1949 में दिए गए लिली मेंथियल के इस सुझाव के आलोक में दो साल बाद 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रोबर्ट ब्लैक भारत पाक के बीच हुआ सिंधु जल समझौते की मध्यस्तता करने के लिए राजी हो गए थे और इस तरह समस्या के तकनीकी पहलुओं की पड़ताल करने अवसर भी हाथ लग गए थे।भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना के रूप में 1973 के चिपको आंदोलन ने भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया तहा। 26 मार्च 1973 को उत्तराखण्ड गढ़वाल के चमोली जिले के रैणी गाँव से स्थानीय महिला गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन पेड़ों को ककतने से बचाने की अलख पूरी दुनिया में जगा दी थी। इसी आंदोलन की बदौलत सुंदरलाल बहुगुणा सरीखे पर्यावरण प्रेमी आंदोलनकारियों ने भी वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान भी बनाई थी।

कर देंगे। पंडित नेहरू भी इस बात से राजी थे , लेकिन जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ और दंगा फसाद के दौर में देश को आजादी मिली तो उनका मन बदल गया था। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर देश का विभाजन पहले ही हो चुका है , ऐसे में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का जोखिम कैसे लिया जा सकता है।

श्रीरामलू ने अक्टूबर 1952 में अपनी मांग के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया था और इसके 36 दिन बाद अनशन के दौरान ही उनका निधन भी हो गया था। उनके निधन की इस घटना ने आंध्र प्रदेश राज्य आंदोलन की मांग को और उग्र बना दिया था। इसे देखते हुए साल १९५३ में आंदोलन की मांग के अनुरूप तत्कालीन मद्रास रेजीडेंसी से अलग कर एक स्वायत्त राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया था। इसी तरह देश के आजाद होने के 14 साल बाद साल 1961 में गोवा आजाद हुआ और भारत का हिस्सा बना था . इसके साथ ही कई अन्य राज्यों के गठन की मांग भी उठने लगी थी। आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन करने समय केंद्र सरकार ने नए सिरे से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से दिसंबर 1953 को एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया था इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर देश के अलग - अलग हिस्सों को अलग - अलग समय में नए राज्यों के रूप में अधिसूचित और स्थापित किया गया था।

हमारे राज्य गठन और पुनर्गठन का संक्षिप्त विवरण

उत्तर प्रदेश : देश के आजाद होने से से पहले संयुक्त प्रान्त ▪ United Province) के नाम से चर्चित, आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से देश के इस सबसे बड़े राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था । इस आशय की घोषणा का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में किया गया था।

बिहार : गुलामी के दौर में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे इस राज्य को 1950 में भारत सरकार के राजपत्र द्वारा अधिसूचित कर स्थापित किया गया था।

असम : 26 जनवरी 1950 इस नाम के साथ अधिसूचित और स्थापित यह इससे पहले असम राज्य नहीं बल्कि असम प्रान्त कहलाता था।

ओडिशा : भारत सरकार के राजपत्र द्वारा साल 1950 में एक राज्य के रूप में अधिसूचित यह राज्य इससे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण वाले बिहार और ओडिशा प्रान्त का हिस्सा था ।

तमिलनाडु : 1 नवंबर 1956 को उस साल के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस नाम के राज्य का गठन इस भूभाग को मद्रास और त्रावणकोर (कोचीन) राज्य से अलग कर किया गया था।

राजस्थान : भारत सरकार की तरफ से 30 मार्च 1949 को जारी की गयी एक अधिसूचना के माध्यम से अस्तित्व में आया यह राज्य अतीत में राजपूताना एजेंसी की रियासत का हिस्सा हुआ करता था ।

आंध्र प्रदेश : 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत अधिसूचित यह राज्य इससे पहले आन्ध्रा बाद राज्य का हिस्सा हुआ करता था।

कर्नाटक : 1 नवंबर 1956 को अपने मौजूदा रूप और नाम से अधिसूचित दक्षिण भारत का यह राज्य अपने उदय से पहले तक हैदराबाद राज्य और मैसूर राज्य का हिस्सा हुआ करता था।

केरल : 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत अधिसूचित यह राज्य अतीत में मद्रास राज्य और त्रावणकोर (कोचीन)राज्य का हिस्सा हुआ करता था।

मध्य प्रदेश : इस राज्य का गठन भी 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था , इस स्वरूप में आने से पहले यह राज्य ए बी और सी तीन अलग अलग श्रेणियों में विभाजित था ।

अरुणाचल प्रदेश : 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1986 के तहत एक स्वायत्त राज्य के रूप में गठित यह राज्य अपने मौजूदा स्वरूप में आने से पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था।

छत्तीसगढ़ : 1 नवंबर 2000 । को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठित यह राज्य इससे पडी में आया यह राज्य इससे पहले मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था।

गोवा : 30 मई 1987 को एक साल पहले के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस राज्य को पूर्ण स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके पहले यह राज्य गोवा , दमन और दीव राज्य का हिस्सा हुआ करता था।

गुजरात : 1 मई 1980 गुजरात को बॉम्बे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य से अलग कर एक पूर्ण स्वायत्त राज्य बनाया गया था।

हरियाणा : 1 नवंबर 1966 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश के पूर्वी पंजाब राज्य से अलग कर इस हिंदी भाषी हरियाणा राज्य का गठन किया गया था।

हिमाचल प्रदेश : देश के आजाद होने के बाद तक पूर्वी पंजाब राज्य का हिस्सा रहे देश के पश्चिमी भाग के इस पर्वतीय क्षेत्रको पहले एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर विकसित किया गया था और बाद में 25 जनवरी 1971 को एक स्वायत्त राज्य बना दिया गया था।

झारखण्ड : बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत बिहार से अलग कर एक नए पूर्ण स्वायत्त राज्य का गठन 15 2000 को किया गया था।

महाराष्ट्र : 1 मई 1960 को अतीत के बॉम्बे राज्य से अलग कर महाराष्ट्र के नाम से नए राज्य का गठन किया गया था।

मेघालय : 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया मेघालय राज्य इससे पहले असम राज्य का हिस्सा था।

मणिपुर : मणिपुर राज्य का गठन भी मेघालय की तरह उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत 21 जनवरी 1972 को ही किया गया था। इस तिथि से पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था।

मिजोरम : 20 जनवरी 1987 को 1986 के मिजोरम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया था।

नागालैंड : पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मौजूद नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को दिया गया था।

पंजाब : अविभाजित भारत के समय से लेकर आजादी के लगभग दो दशक बाद तक पूर्वी पंजाब के रूप में ऐतिहासिक रूप से चर्चित इस राज्य में ही किसी समय हरियाणा , हिमाचल समेत कई राज्य शामिल हुआ करते थे और देश की राजधानी दिल्ली भी इस राज्य का हिस्सा थी। साल 1912 में देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद दिल्ली को पंजाब से अलग कर दिया गया था। बाद के दौर में हरियाणा और हिमाचल को भी अलग राज्यों का दर्जा देकर पूर्वी पंजाब से अलग कर दिया गया था। आजाद भारत में पंजाब के नाम से एक पूर्ण स्वायत्त राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही हो सकी थी ।

सिक्किम : अतीत में स्वतंत्र सिक्किम देश के रूप में पहचान बना कर रखने वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के 36वे संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से एक राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बनाया गया था।

तेलंगाना : 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक के प्रावधानों के आधार इस राज्य का निर्माण किया गया था।

त्रिपुरा : 21 फरवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा पाने वाला यह राज्य इससे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था।

उत्तराखण्ड : 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में इस पर्वतीय राज्य का गठन किया गया था अपने जन्म से पहले यह राज्य देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था।

पश्चिम बंगाल : अविभाजित भारत के एक बड़े राज्य के रूप में चर्चित इसी राज्य के एक हिस्से के रूप में देश के विभाजन के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ था। यही पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांगला देश बन गया था। देश की आजादी के बाद से ही इसे भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के रूप में मान्यता दी गयी थी। भारत के इसी बंगाल राज्य से कालांतर में ओडिशा बिहार जैसे राज्यों के गठन में भी मदद मिली थी।

जम्मू - कश्मीर : 26 अक्टूबर 1947 को भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित इस सीमावर्ती राज्य का अपने जन्म के समय से ही विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही इस राज्य को विशेष अधिकार भी दिए गए थे। देश के आजाद होने के करीब 72साल तक जम्मू कश्मीर विशेष राज्य के रूप में विशेष लाभ लेता भी रहा था। साल 2019 को 31 अक्टूबर का एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाले इस राज्य के विशेष अधिकार एक झटके में ख़त्म कर दिए गए थे और इस पूर्ण स्वायत्त राज्य को क्रमशः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर और केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के रूप में अलग कर दिया गया था। भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश और क्षेत्र में एक बड़ा फ़र्क़ यह होता किकेंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा होती है जबकि केंद्र शासित क्षेत्र विधायिका विहीन होता है। लद्दाख के साथ ही देश में चंडीगढ़ ,लक्ष्यद्वीप , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दादर तथा नागर हवेली ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहाँ विधानसभा नहीं हैं। इसके विपरीत दिल्ली ,पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों / राज्यों के पास अपनी विधानसभाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 में यह व्यवस्था है कि बिना विधानसभा के प्रशासनिक क्षेत्रों में केंद्र यानी राष्ट्रपति का सीधा दखल होता है , लिहाजा इन क्षेत्रों की तमाम गतिविधियों का संचालन केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है।

अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पर बीजेपी गठबंधन को लगेगा झटका

राजनीतिक डेस्क

सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की सजा अदालत से सुनाई गई है। जाहिर है अब उनकी विधायकी भी जाएगी। लेकिन अब्बास अंसारी को जिस अंदाज में सजा दी गई है उससे बीजेपी और बीजेपी की साथी पार्टियों के विधायकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। सुभासपा 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थीं। उस चुनाव में सुभासपा मुखिया ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के दौरान ही अब्बास अंसारी ने एक चुनावी जनसभा में एक विवादित बयान दे दिया था। अब्बास अंसारी ने खुले मंच से अखिलेश यादव का बगैर नाम लिए कहा था कि भैया से बात हो गई है, सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। इस विवादित बयान को बीजेपी ने खूब भुनाया था, उनके इस बयान का विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा था।

वहीं अब्बास अंसारी की अगर विधायकी जाती है तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की संभावना बढ़ जाएगी। जो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब उसके सहयोगी दलों, जैसे अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। इन दलों के तेवर कड़े होने से बीजेपी को गठबंधन की एकता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। इस स्थिति में, सपा के लिए भी अवसर है कि वह उपचुनाव में मजबूत उम्मीदवार उतारकर पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करे। अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्ति न केवल एक व्यक्तिगत नुकसान है, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों और चुनौतियों को जन्म दे सकती है। हालाँकि चुनावी राजनीति को छोड़ भी दें तो जिस ग्तारह से अब्बास अंसारी पर कार्रवाई की गई अगर उसी तरह से यूपी के बाकी दागी विधायकों पर भी कार्रवाई की जाए तो बीजेपी समेत कई पार्टियों के दर्जनों विधायक भी पैदल हो सकते हैं। खासकर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को बड़ा नुक्सान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एडीआर ने चुने गए विधायकों पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी । इसमें खुलासा हुआ किया गया था कि नए विधायकों में 51 फीसदी के दामन पर दाग हैं। 2017 से यह संख्या 15 फीसदी अधिक है। 205 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, 107 एमएलए पर गंभीर आरोप लगे हैं।

राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने की वजह बताने को कहा था। प्रत्याशियों को भी तीन बार इसे सार्वजनिक करना था। लेकिन इससे भी सियासत की तस्वीर नहीं बदली। पिछली बार यानी 2017 में चुने गए 402

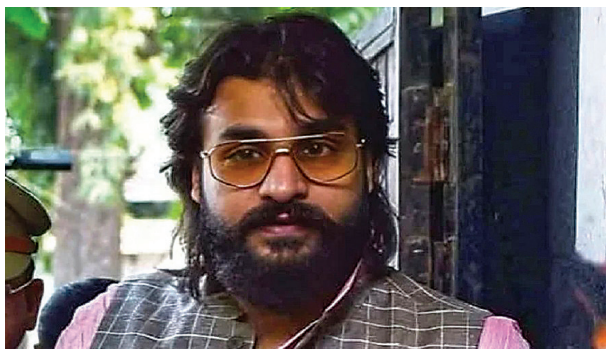

विधायकों में 205 के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं । पिछली बार 143 विधायक आपराधिक छवि के थे। इस बार के 158 विधायक ऐसे हैं जिनके गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। कुल विधायकों का यह 39 फीसदी है। 2017 में 107 विधायकों पर गंभीर अपराधों के आरोप थे। 5 विधायकों के ऊपर हत्या, 29 के ऊपर हत्या के प्रयास और 6 के ऊपर महिला अपराधों से जुड़े मामले दर्ज हैं। इसमें एक विधायक पर रेप तक का आरोप है। पार्टी के आधार पर बात करें तो सपा के 43 फीसदी, भाजपा के 35 फीसदी, रालोद के 63 फीसदी, सुभासपा और निषाद पार्टी के 67-67 फीसदी, अपना दल के 17 फीसदी और कांग्रेस, बसपा व जनसत्ता दल के सभी विधायकों पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं।

न केवल आपराधिक छवि वाले बल्कि करोड़पति विधायकों की भी इस बार भरमार है। इस बार 91 फीसदी विधायक करोड़पति हैं। पिछली बार 80 फीसदी विधायकों की संपत्ति करोड़ से ऊपर थी। सभी विधायकों की संपत्ति का औसत निकाला जाए तो यह आंकड़ा "8 करोड़ प्रति विधायक से अधिक है। 2017 में विधायकों की औसत संपत्ति "5.92 करोड़ थी। 183 विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति "5 करोड़ से अधिक हैं, वहीं, 122 विधायकों की संपत्ति "2 से 5 करोड़ के बीच, 84 विधायकों की संपत्ति "50 लाख से 2 करोड़ तो महज 12 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति "10 लाख से 50 लाख के बीच बताई है। दोबारा चुनकर आने वाले विधायकों की औसतन संपत्ति बढ़कर "8.28 करोड़ रुपये पहुंच गई है। 2017 में इनकी संपत्ति का औसत "8.28 करोड़ था। में सवाल उठता है कि जिस मामले में अब्बास अंसारी के ऊपर कार्रवाई की गई ,बाकी दागी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अगर अदालत की तरफ से दागी सभी उम्मीदवारों पर ठीक ऐसे ही कार्रवाई की जाए तो बीजेपी को बड़ा नुक्सान हो सकता है। उसके सौ से ज्यादा विधायक पैदल हो सकते हैं और जेल के पीछे बंद भी हो सकते हैं। क्या बीजेपी ऐसा चाहेगी ?और क्या कोर्ट उन सभी दागियों पर भी कार्रवाई करेगी ?

मायावती ने आजाद समाज पार्टी को क्यों बताया बरसाती मेंढक?

राजनीतिक डेस्क

बसपा प्रमुख मायावती ने भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर करारा हमला करते हुए उनकी पार्टी की तुलना बरसाती मेंढक से की है। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन न सिर्फ बसपा को कमजोर करते हैं बल्कि ऐसी पार्टियों का कोई भविष्य भी नहीं होता। ये बरसाती मेंढक जैसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव के समय दिखती हैं। हालाँकि जानकार मान रहे हैं कि चंद्रशेखर की राजनीति से बसपा प्रमुख घबरा सी गई है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे संगठनों ने बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश की है और ये पार्टी बरसाती मेंढक की तरह है जो बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती।उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी देश में बहुजन हितों की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है।

पार्टी में अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से राष्ट्रीय संयोजक बनाने के अपने कदम का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हित में कोई भी कदम वापस लेने की परंपरा रही है और इसी क्रम में आकाश आनंद को फिर से राष्ट्रीय संयोजक बनाने से अन्य दलों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है।उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश आनंद बहुजन समाज के स्वाभिमान के कारवां को आगे बढ़ाने और डॉ. भीमराव अंबेडकर व कांशीराम के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना मायावती ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि पार्टियों के साथ चलने से बहुजनों की एकता को ये बरसाती मेंढक नहीं तोड़ सकते जो बसपा को भी कमजोर नहीं कर सकते। दरअसल आजाद ने कहा था कि जनता ने आकाश आनंद को नकार दिया है और अब मजबूरी में उन्हें पहले हटाया गया और फिर से बहाल किया गया क्योंकि बसपा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आजाद ने कहा, "मैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का सम्मान करता हूं। हमारी पार्टी अब कांशीराम और भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करेगी।" चंद्रशेखर आजाद ने बसपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहब डॉ. अंबेडकर कहते थे कि मुर्दे मिशन नहीं चलाते और जिंदा रहते मिशन नहीं छोड़ते।

धामी सरकार की नई कवायद पहाड़ पर बसेंगे नए शहर

न्यूज़ डेस्क

उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ों में नए शहरों के विकास की योजना बनाई है। पौड़ी जिले के बिल्वकेदार (श्रीनगर) में नए शहर की स्थापना की जाएगी। नए शहरों के विकास से पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों से निरंतर हो रहे पलायन को थामने की कड़ी में सरकार ने पहाड़ों में नए शहर विकसित करने के लिए कसरत शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पौड़ी जिले के अंतर्गत बिल्वकेदार (श्रीनगर) में नया शहर बसाने की योजना है।आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार इस संबंध में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि वह इसी माह कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया पूरी कर नए शहर की महायोजना व माडल तैयार कर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

पहाड़ में विकसित किए जाएंगे नए शहर

आवास विभाग के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र में नए शहरों की परिकल्पना पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित कराया गया था। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में नए शहरों की तरफ कदम बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य में नई टिहरी के बाद अन्य कोई नया शहर अब तक नियोजित रूप से नहीं बन सका है। उन्होंने कहा कि अब आवास विभाग के माध्यम से नए शहर की परिकल्पना कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस कड़ी में बिल्वकेदार में नया शहर स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्र में भी नए शहर की स्थापना के लिए भूमि चयन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सजग नागरिक सुशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है। आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय से मिले, इसके लिए सरकारी कार्मिकों को सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा व सुशासन को प्राथमिकता देनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उत्तराखंड इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र व राज्य सरकार ने कई जनोपयोगी योजनाएं बनाई हैं तथा कई नीतियों में आवश्यक संशोधन भी किया है।

अखिलेश यादव के पीडीए के मुकाबले के लिए बीजेपी का हिंदुत्व दांव

राजनीतिक डेस्क

उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं लेकिन वहां अभी से ही राजनीतिक गोटियां फिट की जा रही है। सूबे के हर इलाके में चुनाव की बात हो रही है। सपा जहाँ पीडीए के सहारे बीजेपी को मात देने की रणनीति पर गहराई से काम कर रही है वही अब बीजेपी और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सहारे ही सपा के खेल को ख़त्म करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए के सहारे यूपी में बीजेपी को बड़ी मात देते हुए अपनी खास उपस्थिति को दर्ज करते हुए सबको चकित कर दिया था। सपा के इस रंग ढंग से बीजेपी भी चकित हो गई थी। बीजेपी को इसका भान तक नहीं था कि पीडीए का खेल बीजेपी पर भारी पडेगा। लेकिन अब बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले अस्त्र को ही और धारदार कर रही है। बीजेपी को पता है कि हिंदुत्व के सहारे ही अब तक उसकी सरकार बनती और चलती रही है। ऐसे में अगर हिंदुत्व को और भी तेज किया जाय तो सपा के खेल को ध्वस्त किया जा सकता है। अब बीजेपी फिर से हिंदुत्व को धारदार बनाती दिख रही है। बीजेपी का यह नया हिंदुत्व सपा के पीडीए पर कितना घातक साबित हो सकता है इस पर सबकी निगाहें टिक गई है।

अहिल्याबाई होल्कर के जरिये पाल -बघेल पर नजर

बीते 31 मई को उत्तर प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई गई। अहिल्याबाई होलकर जयंती पर इतने आयोजन उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं देखे गए। होलकर इंदौर की महारानी थीं। किसान परिवार में पैदा हुईं होलकर गड़ेरिया-चरवाहा जाति की थी। उत्तर प्रदेश में

बीजेपी ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के लिए उन इलाकों का खासतौर पर चयन किया, जहां पाल-बघेल-गड़ेरिया जाति की आबादी अधिक है। मुख्य समारोह आगरा में रविवार को आयोजित किया गया. इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके जरिए पाल-बघेल-गड़ेरिया जैसी जातियों को साधने की कोशिश की गई। इन जातियों की आबादी आगरा और अलीगढ़ मंडल में अधिक है।

सुहेलदेव के जरिए हिंदुत्व पर निशाना

तराई के बहराइच जिले में हर साल मई में सैयद सालार मसूद गाजी का मेला (जेठ मेला) लगता था। इस साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर रोक दिया था। यह मामला कानूनी पचड़े में पड़ा, लेकिन लग नहीं पाया.अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाने जा रही है। महाराजा सुहेलदेव ने 10 जून 1034 को बहराइच के नानपारा मैदान में हुई लड़ाई में महमूद गजनवी के भतीजे और सेनापति सैयद सालार गाजी को मार गिराया था। सुभासपा सुहेलदेव को राजभर जाति का बताती है। वह जिस मेले का आयोजन कर रही है, उसके मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ होंगे। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस मेले का वर्चुअल उद्घाटन कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुभासपा की राजनीति राजभर जाति के आसपास होती है। ओबीसी में आने वाली इस जाति के वोट यूपी के पूर्वांचल के जिलों में अच्छे खासे हैं। बीजेपी सुभासपा के जरिए राजभरों को साधने की कोशिश कर रही है। इसी के सहारे बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की भी कोशिश कर रही है।

जाति जनगणना कराने का फैसला

नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जाति जनगणना कराने के लिए गए फैसले को भी अखिलेश यादव के पीडीए और कांग्रेस की ओर से आरक्षण पर खतरे के नैरेटिव को कुंद करने का प्रयास के रूप में ही देखा जा रहा है। देश में जाती जनगणना कराने की मांग सबसे अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की ओर से ही की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए फार्मूले के सहारे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी मात दी थी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के साथ सपा के हौंसले बुलंद हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जोर-शोर से पीडीए की बात कर रहे हैं। इसी फार्मूले के सहारे अखिलेश 2027 में जीत के बाद उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी उनके इस दावे को पंचर करना चाहती है, इसलिए वह अपने स्तर पर पीडीए के फार्मूले को ध्वस्त कर उसका काट निकालने में जुटी हुई है। अब इस दिशा में सपा को कितना फायदा होता है और बीजेपी कितना फायदा उठा पाती है,उसका पता हमें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों में ही नजर आएगा।

नेताम की नयी राजनीति से कांग्रेस परेशान

राजनीतिक डेस्क

पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रभावशाली आदिवासी नेता, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी, ने कहा कि वे धर्मांतरण के मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस आदिवासियों के विचारों को स्वीकार करता है। आरएसएस द्वारा अपने नागपुर मुख्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम को आमंत्रित किए जाने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री जो बस्तर क्षेत्र से आते हैं, 5 जून को संघ के "कार्यकर्ता विकास वर्ग-द्वितीय समापन समारोह" में मुख्य अतिथि होंगे। यह स्वयंसेवकों या संघ कैडर के लिए तीन साल के प्रशिक्षण की अवधि का समापन है। यह वही कार्यक्रम है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2018 में भाग लिया था, जिसके कारण कांग्रेस के कुछ वर्गों ने आलोचना की थी।

आमंत्रण से राजनीतिक उद्देश्यों के बारे में सवाल उठने के साथ, 83 वर्षीय आदिवासी नेता ने कहा कि उन्होंने संघ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और बस्तर में आदिवासी अधिकारों के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए भाग लेने की योजना बनाई है। नेताम ने कहा, "मैं आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरएसएस के साथ मजबूत संवाद हो ताकि वे आदिवासी मुद्दों को समझ सकें। बस्तर में अभी सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण है। मेरा मानना है कि अगर आरएसएस हमारा समर्थन करता है, तो भाजपा सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी। हम ही हैं जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने आदिवासी कार्यक्रम में सबसे पहले आरएसएस

छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता अरविंद नेतामजो कांग्रेस छोड़ चुके हैं अब आरएसएस कार्यक्रम में शामिल हो कर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। नेताम का यह कदम कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है।

नेताओं को आमंत्रित किया था। इसके अलावा, महीनों पहले, मैंने रायपुर में मोहन भागवत से मुलाकात की और आदिवासी मुद्दों पर चर्चा की।"

नेताम ने कहा कि वह जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग कोड की आवश्यकता पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, "हमारी अपनी संस्कृति और धार्मिक प्रथाएं हैं। हम किसी धर्म के तहत परिभाषित नहीं होना चाहते; हम अपना कोड चाहते हैं। बातचीत के कारण धीरे-धीरे बदलाव हो रहे हैं। वे (आरएसएस) धीरे-धीरे हमें आदिवासी कह रहे हैं, वनवासी नहीं।" बता दें कि बस्तर में एक प्रभावशाली आदिवासी नेता नेताम अभी भी काफी राजनीतिक दबदबा रखते हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। यह तब हुआ जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी हमार राज बनाई, जिसे उन्होंने आदिवासी संगठनों के एक छत्र समूह सर्व आदिवासी समाज (एसएएस) से अलग करके बनाया था। उस समय, नेताम ने कहा था कि हमार राज का गठन संघ के गठन जैसा ही है, जिसके अंतर्गत "भाजपा सहित 50 से अधिक स्वतंत्र समूह हैं"।

चुनावों में, हमार राज ने कम से कम दो विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया और अनुमान है कि इससे लोकसभा चुनावों में कांकेर संसदीय सीट पर कांग्रेस की संभावनाओं को भी नुकसान पहुँचा है। नेताम का संघ की ओर स्पष्ट कदम ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पहले से ही आदिवासी वोटों को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। जब पार्टी 2018 में सत्ता में आई थी, तो उसने अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में 29 में से 25 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को तीन सीटें मिली थीं। हालांकि, आदिवासी मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफलता के कारण आदिवासियों के बीच कांग्रेस की जमीन खिसक गई और 2023 में, कांग्रेस की एसटी सीटों की संख्या घटकर 11 रह गई, जबकि भाजपा को 17 सीटें मिलीं। हालांकि, कांग्रेस का तर्क है कि भले ही नेताम भाजपा में चले जाएं, लेकिन इससे उसके राजनीतिक भाग्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्टी के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, "उन्होंने (नेताम) अलग राजनीतिक रास्ता अपनाया और पार्टी छोड़ दी। वे एक बड़े आदिवासी नेता हैं, लेकिन हम आदिवासियों के बारे में आरएसएस के नजरिए को जानते हैं। आरएसएस आदिवासियों को वनवासी (वनवासी) कहता है, आदिवासी (सबसे बुजुर्ग निवासी) नहीं। तो क्या नेताम इससे सहमत हैं? राजनीतिक रूप से, इससे चुनावों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा... बस्तर की जनता उनका समर्थन नहीं करती।"

छत्तीसगढ़ में करणी सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर के घर से करोड़ों की नकदी बरामद

न्यूज़ डेस्क

करणी सेना के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उनके भाई हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर के आवासों पर क्राइम ब्रांच ने पिछले सप्ताह ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई में पुलिस ने कई करोड़ रुपये की नकदी, दो किलो सोना, दो पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस, एक लग्जरी गाड़ी और जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। छापेमारी की यह कार्रवाई रोहित तोमर के खिलाफ दर्ज पुराने आपराधिक मामलों और आर्थिक गड़बड़ियों की जांच के तहत की गई । रोहित को स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड में एक सक्रिय हिस्ट्रीशीटर बताया गया है।सुरक्षा कारणों को देखते हुए कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह छापा किसी बड़े आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क से जुड़े सुराग सामने ला सकता है।

क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद करणी सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी तोमर और उनके भाई रोहित सिंह तोमर रायपुर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, रोहित का मोबाइल बंद है और उसके साथ उसका निजी बाउंसर भी लापता है। दोनों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ रायपुर के अलग-अलग थानों में सूदखोरी, जबरन वसूली, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अपहरण, और गोलीबारी जैसे 12 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। वे कई बार जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर थे, लेकिन जमानत के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। रोहित तोमर शहर में 'गोल्डमैन' के नाम से कुख्यात है। उसने सूदखोरी से अर्जित पैसों से लाखों का सोना खरीदा और सोने के गहनों के साथ शाही अंदाज में घूमता है। भाठागांव में उसका आलीशान बंगला है और शहर के कई हिस्सों में करोड़ों की संपत्तियां, महंगी गाड़ियां और निजी सुरक्षा गार्डों की फौज उसके रसूख को दर्शाती है। इनके खिलाफ वीआईपी रोड, भाठागांव, कबीर नगर, कोतवाली, आजाद चौक, गुढियारी, अमलीडीह व हलवाई लाइन समेत कई थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज हैं।

मंत्री को महंगा पड़ गया राहुल गांधी पर कमेंट, कांग्रेस ने खोला कच्चा चिट्ठा

राजनीतिक डेस्क

पिछले दिनों राहुल गाँधी भोपाल के दौरे पर थे। उन्होंने पार्टी के लोगों को सम्बोधित किया और बीजेपी से लेकर पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। राहुल गाँधी फिर लौट गए। बाद में बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री ने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। अब कांग्रेस उस मंत्री को ही लपेटे में ले रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मंगलवार का भोपाल दौरा अभी भी चर्चा में बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी पर उनका बयान सुर्खियों में है। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी को बचकाना बताते हुए उनकी घोर निंदा की है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता जिस तरह से मर्यादा को ताक पर रखकर बोल रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने तो इस बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ा कमेंट कर दिया। हालांकि यह कमेंट उन्हें महंगा पड़ गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग

सिंघार ने मंत्री तुलसीराम सिलावट को उनकी कांग्रेसी पृष्ठभूमि की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस की ही कृपा से वे चार दशक तक पार्षद से लेकर मंत्री तक बने।

सांवेर से विधायक और प्रदेश के जल संसाधन विभाग के केबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस में परिवारवाद को लेकर राहुल गांधी को घेरा है ।मंत्री तुलसी सिलावट ने पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर अपने एक्स हेंडल पर कमेंट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा—"जी हुजूर " का सार्थक अर्थ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बेहतर कौन समझ सकता है। जब सदियों तक उन्होंने एक ही परिवार की जी हुजूरी करनी पड़ी। इमरजेंसी की जी हुजूरी, पीओके छोड़ने की जी हुजूरी, चीन की जी हुजूरी। कई ऐसी विदेशी आक्रांताओं की जी हुजूरी जो देश के लिए खतरनाक साबित हुई।

आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अनर्गल बयान देने से क्या राहुल जी कांग्रेस के कर्मों को छुपा सकते हैं? इसपर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में मंत्री तुलसी सिलावट को उनका कांग्रेसी अतीत याद दिलाया। उमंग सिंघार ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा— तुलसीराम सिलावटजी,मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1982 से 2020 तक करीब 40 साल आप भी कांग्रेस परिवार के सदस्य रह चुके हैं। सामान्य कार्यकर्ता से लेकर पार्षद, 4 बार विधायक और मंत्री बनने तक का मौका इसी पार्टी ने आपको दिया।

मुझे गर्व है कि कांग्रेस में ऐसे असंख्य बब्बर शेर मौजूद हैं जिन्होंने पद और पैसे की लालसा में रातों-रात अपनी वैचारिक निष्ठा की बलि नहीं दी और आज भी जनता के हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिन-रात तत्पर हैं।इतिहास को भूलना अवसरवाद ही नहीं, अहसान फरामोशी भी है।

पत्रकारिता को नए सिरे से परिभाषित करते हुए न्यू देहली पोस्ट की शानदार प्रस्तुति अब आपके सामने है। इसमें होगी खोजी और जानबूझ कर दबाई गई ख़बरों के उद्भेदन की शानदार प्रस्तुति - न्यू दिल्ली पोस्ट प्रिंट और डिजिटल के सभी मंचो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है :-

न्यू देहली पोस्ट
(साप्ताहिक हिंदी)

हमारे ये सभी डिजिटल मंच सभी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। यहाँ जाकर आप ताजातरीन ख़बरों और विश्लेषण को देख समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं।

Website: https://newdelhipost.co.in/
: @NewDelhiPost
: https://www.facebook.com/NewDelhiPosts
: @NewDelhiPost
:newdelhipost_official

न्यू देहली पोस्ट
B-614, 6th Floor Tower B
Noida One Building
Noida Sector 62, Gautam Budh Nagar (UP)
Pin Code -201309

संपर्क करे - Email - postnewdelhi@gmail.com

इज़रायल ने हमास को दी विनाश की चेतावनी

वरिष्ठ संवाददाता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गाजा युद्ध विराम के करीब पहुंचने की घोषणा के बाद इजरायल ने हमास को विनाश की धमकी दी है।

इजरायल ने पिछले दिनों कहा कि हमास को गाजा में बंधक समझौते को स्वीकार करना चाहिए या फिर "खत्म कर दिया जाएगा। '' उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि युद्ध विराम समझौता "बहुत करीब" है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब जमीन पर हालात बहुत खराब हैं, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा की पूरी आबादी अकाल के खतरे में है। इजरायल के रक्षा मंत्री कैट्ज ने कहा कि हमास को अमेरिकी दूत विटकॉफ के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। अन्यथा उसे नष्ट हो जाना होगा। हमास ने दावा किया है कि यह समझौता उसकी मांगों को पूरा नहीं करता है।

युद्ध विराम पर हस्ताक्षर

व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि इजरायल ने हमास को सौंपे गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर "हस्ताक्षर" कर दिए हैं। फिलिस्तीनी समूह ने कहा कि यह समझौता उसकी मांगों को पूरा करने में विफल रहा। साथ ही उसने इसे पूरी तरह से खारिज करने से परहेज किया। साथ ही ये कहा कि वह प्रस्ताव पर "विचार-विमर्श" कर रहा है। रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने कहा कि हमास को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत होना चाहिए। या फिर उसे बर्बाद हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा कि फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह ने कहा कि यह समझौता उसकी मांगों को पूरा रने में विफल रहा है। कैट्ज ने कहा "हमास के हत्यारों को अब यह चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बंधकों की रिहाई के लिए 'विटकॉफ डील' की शर्तों को स्वीकार करें - या नष्ट हो जाएं। " इज़राइल ने बार-बार कहा है कि हमास का विनाश युद्ध का मुख्य उद्देश्य था. गाजा में लगभग 20 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता अब तक सफल नहीं हो पाई है। इज़राइल ने मार्च में एक अल्पकालिक युद्ध विराम के बाद अभियान फिर से शुरू किया।

यहूदी इजरायली राज्य

शुक्रवार को, कैट्ज ने वेस्ट बैंक में "यहूदी इजरायली राज्य" बनाने की कसम खाई। फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है और दशकों से चल रहे इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में स्थायी शांति के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। इससे पहले एक रैली में बंधकों की रिहाई और युद्ध की समाप्ति की मांग की गई। यह रैल 28 मई को इजरायल के तेल अवीव में बंधक चौक के रूप में जाने जाने वाले एक प्लाजा में आयोजित की गई। हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 18 मार्च को इजरायल द्वारा सैन्य अभियान पुनः शुरू करने के बाद से कम से कम 4,058 लोग मारे गए हैं। इस तरह से युद्ध में मरने वालों की कुल संख्या 54,321 हो गई है, जिनमें अधिकतर नागरिक हैं। आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना के मुताबिक, हमास द्वारा 2023 में इजरायल पर किए गए हमले में 1,218 लोगों की मौत हुई। इनमें से अधिकतर नागरिक थे. वहीं हमास के हमले के दौरान पकड़े गए 251 बंधकों में से 57 गाजा में ही रह गए हैं। इनमें से 34 के बारे में इजरायली सेना का कहना है कि वे मर चुके हैं।

पलटी मार राष्ट्रपति ट्रंप !

वरिष्ठ संवाददाता

ट्रम्प 130 दिन में अपने 11 फैसले पलट चुके हैं। इसके बाद 180 फैसले को कोर्ट ने रोके; प्रशासन के आदेशों के खिलाफ 150 से ज्यादा याचिका दायर।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए अभी सिर्फ 132 दिन ही हुए हैं। लेकिन उनकी नीतियों को लेकर विवाद और कानूनी चुनौतियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं।अब तक अमेरिकी अदालतों ने ट्रम्प प्रशासन के कम से कम 180 कार्यकारी आदेशों और नीतियों पर स्थायी या अस्थायी तौर पर रोक लगाई है। साथ ही, ट्रम्प ने खुद 11 प्रमुख फैसलों पर यू-टर्न लेते हुए पलटा है। रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने, संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी और विदेशी सहायता रोकने जैसे आदेशों को अवैध या असंवैधानिक ठहराया है।वहीं, ट्रम्प ने फेडरल फंडिंग फ्रीज, अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा और टैरिफ नीतियों जैसे फैसलों को कई बार बदला या वापस लिया है।ट्रम्प प्रशासन के आदेशों के खिलाफ अब तक 250 से अधिक याचिका दायर की जा चुकी है।

ट्रम्प के वो आदेश जिन्हें कोर्ट ने बदला

ट्रम्प ने वॉयस ऑफ अमेरिका को खत्म करने का फैसला लिया था, जिसे कोलोराडो की अदालत ने अवैध ठहराया। पर्यावरण नियमों को कमजोर करने वाले आदेशों को भी कैलिफोर्निया की अदालत ने रोका। वजह- वे क्लीन एयर एक्ट का उल्लंघन करते थे। वाशिंगटन की अदालत ने गैर अमेरिकियों के लिए मतदान प्रतिबंध को असंवैधानिक माना। अप्रैल 2025 में एक हफ्ते में 11 मुकदमों में ट्रंप प्रशासन को हार मिली।ट्रम्प के ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य अधिकारों को सीमित करने वाले आदेश को भी न्यूयॉर्क कोर्ट ने भेदभावपूर्ण ठहराते हुए अवैध ठहराया। इसके अलावा ट्रम्प के विदेशी फंडिंग से जुड़े आदेश को भी अदालत ने गलत माना।

ट्रम्प ने जिन नीतियों को बार-बार पलटा उनमें सबसे बड़ा मामला टैरिफ से जुड़ा है। साथ ही प्रवासी बच्चों की बर्थ राइट रोकने का फैसला भी आदेश के कुछ दिनों के भीतर ट्रम्प ने रद्द कर दिया।डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के तहत इबोला रोकथाम फंडिंग रद्द हुई, जिसे बाद में फिर बहाल किया गया। मेक्सिको-कनाडा के साथ व्यापार समझौते को रद्द करने की घोषणा की लेकिन दबाव के बाद इसे स्थगित किया।

मस्क और ट्रंप में टकराव बढ़ा

कभी ट्रम्प के चुनावी अभियान में 2100 करोड़ रुपए का चंदा और खुलेआम समर्थन देने वाले कारोबारी इलॉन मस्क ने ट्रम्प से अलग होने का फैसला किया है। इसकी बड़ी वजह मस्क का चीन में कारोबारी हित का जुड़ाव होना है।मस्क-ट्रम्प की तकरार की शुरुआत मार्च 2025 में पेंटागन की मीटिंग है। दरअसल, मस्क अपने हित साधने को चीन पर अमेरिका की खुफिया नीति, जिसमें वॉर प्लान तक शामिल हैं की जानकारी चाहते थे। ट्रम्प ने ये साझा करने से मना कर दिया। बता दें कि मस्क की ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला चीन पर काफी हद तक निर्भर है। टेस्ला कंपनी के कारों में लगने वाली 40% बैटरी व 25% कलपुर्जे चीन से आते हैं।

चीन ने अंतरराष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए नया संगठन बनाया

इंटरनेशनल डेस्क

चीन ने बीते शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए एक नया संगठन बनाया है। इसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन यानी आईओमेड है। इसे इंटरनेशनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। इसमें 85 देशों और लगभग 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के करीब 400 बड़े अधिकारी शामिल हुए। इनमें से 33 देशों ने तुरंत हस्ताक्षर करके IOMED के संस्थापक सदस्य बन गए।चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आईओमेड को मध्यस्थता के जरिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने वाला दुनिया का पहला 'सरकारों के बीच का कानूनी संगठन' (इंटर-गवर्नमेंटल कानूनी संगठन) बताया।

नए संस्था का दफ्तर हांगकांग

चीन समेत 33 देश इस संगठन के संस्थापक सदस्य बने। हेड ऑफिस हॉन्गकॉन्ग में होगा। हॉन्गकॉन्ग में आयोजित एक हाई लेवल समारोह में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने आईओमेड की स्थापना के समझौते को औपचारिक रूप दिया।इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा और कंबोडिया उन 33 से देशों में शामिल थे, जो चीन के साथ इस संगठन के संस्थापक सदस्य बने।हॉन्गकॉन्ग सरकार के प्रमुख जॉन ली ने कहा कि उनकी सरकार आईओमेड को हर तरह से समर्थन देगी, ताकि ये संगठन जल्द और भरोसेमंद हल निकाल सके।

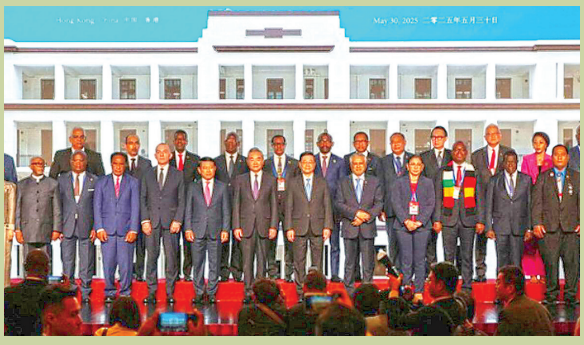

आईओमेड : 30 मई 2025 को चीन ने हॉन्गकॉन्ग में इसकी स्थापना की है। इस संस्था पर चीन का प्रभाव ज्यादा है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया समेत 30 देश संस्थापक सदस्य बने हैं। इसका मकसद सिर्फ मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का है। समझौता स्वैच्छिक होगा, अगर कोई पक्ष सहमत नहीं हुआ तो कोई फैसला नहीं होगा। इसमें देशों के साथ साथ दूसरे देश के नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन मामले दायर कर सकते हैं।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसः

इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 15 जज होते हैं, जिन्हें यूएन महासभा और सुरक्षा परिषद 9 साल के लिए चुनते हैं। यह यूएन चार्टर के तहत काम करता है, सभी यूएन सदस्य देश इसके मेंबर होते हैं। यह एक औपचारिक अदालत है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर बाध्यकारी फैसले देती है। सिर्फ देश ही इसमें मामले दायर कर सकते हैं।

सिर्फ मध्यस्थता के लिए काम करेगा

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन दुनिया के मुद्दों को बातचीत और समझदारी से हल करना चाहता है, लड़ाई-झगड़े से नहीं।उन्होंने कहा आईओमेड की स्थापना 'तुम हारो, मैं जीतूं' की सोच को पीछे छोड़ने में मदद करेगी।इसका मकसद देशों के बीच और दूसरे देश के नागरिकों के बीच, या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों के बीच विवादों को हल करना है। यह सिर्फ मध्यस्थता के जरिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि इस संगठन की स्थापना तुम हारो, मैं जीतूं की सोच को पीछे छोड़ने के लिए हुआ था। माना जा रहा है कि ग्लोबल साउथ में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स को आशंका है कि चीन की इस पहल से कई विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ में चीन का प्रभाव बढ़ सकता। हालांकि, इस संगठन के कामकाज को लेकर अभी कोई साफ जानकारी नहीं है। चीन की कर्ज नीति और विस्तारवादी रवैए की वजह से इस संगठन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, चीन ने दावा है कि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करेगा।

बिहार चुनाव में आप की इंट्री
महागठबंधन की बढ़ेगी मुश्किलें

राजनीतिक डेस्क

अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप बिहार विधान सभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेग,इसका ऐलान हो गया है। इस ऐलान के साथ ही यह भी साफ़ हो गया कि बिहार में इंडिया गठबंधन बिखर गया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप के इस फैसले से इंडिया गठबंधन को नुकसान होने की सम्भावना बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी जिस संकल्प के साथ 'चुनावी जंग' में उतर रही है, वह 'इंडिया' गठबंधन के टूट जाने के संदेश के साथ महागठबंधन के नायक तेजस्वी यादव के लिए ठीक नहीं है। इस टूट का सीधा फायदा बिहार चुनाव में राज्य की नीतीश नीत एनडीए सरकार को होने जा रहा है। आदमी पार्टी का प्लान?

आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर खुद को 'इंडिया ' गठबंधन से अलग कर विपक्ष के रणनीतिकारों को चौंका डाला है। यह दीगर है कि 'इंडिया' गठबंधन के भीतर कई लोगों ने अपनी डफली राग अलापना पहले ही शुरू कर दिया था। अब 'आप' ने भी यह कहा कि 'इंडिया' गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की पार्टी अपना अलग दृष्टिकोण के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। हाल ही के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ी थी। मिली जानकारी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वे प्रमुख किरदार हैं, जो विधान सभा चुनाव 2025 को लेकर अपने दम पर चुनावी अभियान के लिए रणनीति बना रहे हैं।

महागठबंधन के वोटों में बिखराव?

राजनीतिज्ञों की माने तो समग्रता में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के 243 सीटों पर तात्कालिक रूप से लगता है कि महागठबंधन के वोटों में बिखराव स्पष्ट है। इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग-अलग चुनाव लड़ना, भाजपा की सरकार बनने का एक मुख्य कारण बना था। बिहार में भी 'आप' का अलग होना महागठबंधन के वोट विभाजन के कारण बन सकता है। हालांकि ये बिखराव तब और स्पष्ट होगा, जब आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। बिहार के जातीय समीकरण में आम आदमी पार्टी किस सोशल इंजीनियरिंग के साथ उम्मीदवार उतारेगी, वह वोट बंटवारा का कारण बनेगा।

पार्टी का उद्देश्य?

आम आदमी पार्टी इस चुनावी अभियान के जरिए विधानसभा में खाता खोलने की तैयारी कर रही है। लेकिन इनके निशाने पर वर्ष 2030 का विधानसभा चुनाव है।इस चुनाव में पार्टी प्राप्त वोटों के सहारे अपना मत प्रतिशत बढ़ाना चाहती है, ताकि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए सहायक हो। दरअसल एक नेशनल पार्टी बनने के लिए कई तरह के कैटेगरी रखी गई हैं। पहला ये है कि किसी भी पार्टी की कम से कम तीन राज्यों में लगभग 11 लोकसभा सीटें होनी चाहिए। इसके अलावा एक कैटेगरी ये भी है कि अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी की कैटेगरी में शामिल हो जाती है तो उसे मान्यता मिल जाती है। अब राज्य पार्टी की कैटेगरी में शामिल होने के लिए पार्टी को एक राज्य के विधानसभा चुनाव में 6 प्रतिशत वोट/2 सीटें निकालनी होती हैं। अगर उसका वोट प्रतिशत 6 से कम है तो सीटों की संख्या 3 होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को चार राज्यों-दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। तब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में थी। अब दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई है। अब बिहार उनका नया ठिकाना बना है।

बिहार चुनाव आते -आते राजनीतिक खेल कितना बदलेगा यह अभी कोई नहीं जानता। इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई तो साफ़ दिख रही है लेकिन जन सुराज की राजनीति भी कम घातक नहीं है। फिर दोनों गठबंधन में भी दरार की सम्भावना है। लेकिन इससे इतर अभी आम आदमी पार्टी ने जिस अंदाज में बिहार की चुनावी रण में उतरने का फैसला किया है वह इंडिया गठबंधन की टूट की कहानी को आगे बढाती है और महागठबंधन की मुश्किलों को भी बढाती दिख रही है।

आप की तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी के रणनीतिकार काफी गंभीर है। वह जानते हैं, अकेले दम पर लड़ना और बेहतर परफॉर्म करना आसान नहीं है। इसलिए जातीय जकड़न से भरे चुनावी समीकरण को समझने के लिए आम आदमी पार्टी भी बिहार में पद यात्रा की राह चल पड़ी है। राज्य में आम आदमी पार्टी ने अपनी पद यात्रा की शुरुआत 31 मई से कर दी है। यह पदयात्रा सात चरणों में होगी। आम आदमी पार्टी ने इस पदयात्रा को 'केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा' का नाम दिया है। इस पद यात्रा के दौरान जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार अभी अपनी पैठ बनाने में लगे हैं।

चिराग लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, लगाएंगे दांव

राजनीतिक डेस्क

बिहार में चुनावी दुदुम्भी बजने लगी है। हालांकि बिहार में चुनाव अक्टूबर -नवंबर में होने हैं लेकिन बिहार के दोनों गठबंधन की तरफ से जनता को जगाने और जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की हर कोशिश की जा रही है। इसी बीच पिछले कई दिनों से एक खबर चल रही है कि लोजपा नेता चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। वे तीन बार से सांसद बनते रहे हैं। चिराग खुद को मोदी का हनुमान भी कहते रहें हैं। लेकिन अब चिराग का मन बदलना और विधान सभा चुनाव लड़ने की बात कहना कई सवालों को जन्म दे रहा है।

पहला सवाल तो यही है कि क्या चिराग पासवान खुद को सीएम के रूप में पेश करने को आतुर हैं ? क्या उन्हें लग रहा है कि इस बार के बिहार चुनाव में कुछ भी हो सकता है और अगर जदयू का खेल फिर दसे ख़राब होता है तो बीजेपी उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा सकती है ? दूसरा सवाल यह है कि अगर बिहार के लोग इस बार बीजेपी को झटका देते हैं और जदयू की स्थिति पहले से बेहतर होती है तो उस हाल में भी चिराग को लाभ हो सकता है। कुछ सीटें जीतकर भी वे सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और सीएम की कुर्सी तक भी पहुँच सकते हैं।

तीसरा बड़ा सवाल महागठबंधन को लेकर भी है। अभी का जो माहौल है उसमे राजद नेता तेजस्वी यादव सीएम के रूप में सूबे की पहली पसंद है। कई सर्वे इसी तरफ इशारा कर रहें हैं। ऐसे में चिराग पासवान दर्जन भर सेटों को जीतकर भी आते हैं तो उनकी महत्ता काफी बढ़ सकती है। यहाँ भी वे सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। महागठबंधन की पूरी राजनीति इस बात पर टिकी है कि चाहे जैसे भी हो बीजेपी के हाथ में सत्ता न जाए। ऐसी हालत में चुनावी परिणाम अगर हंग वाली होती है तो चिराग की पूछ महागठबंधन की तरफ से बढ़ सकती है और वे फिर शर्तों के मुताबिक महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में चिराग और प्रशांत किशोर पर सबकी निगाहें टिकी रहेंअभी नीतीश के साथ गी। इनके बिना कोई भी बगथबन्धन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो सकती है। ऐसे में चिराग पासवान की पहली कोशिश तो यही है कि वे एनडीए में रहते हुए भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। लेकिन क्या यह सब संभव है ? क्या जदयू और बीजेपी चिराग की पार्टी को अधिक सीटें देने को तैयार है ? हरगिज भी नहीं। जदयू तो किसी भी सूरत में चिराग की पार्टी को दर्जन भर भी सीटें देने को तैयार नहीं हो सकती। और बीजेपी की बात की जाए तो वह भी ऐसा नहीं करेगी। क्योंकि बीजेपी अगर ऐसा करती है तो पार्टी में बिखराव हो सकता है। पार्टी से कई नेता निकल सकते हैं और ऐसा हुआ तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है।

बिहार चुनाव में चिराग पासवान भी मैदान में उतरने को व्याकुल हैं। उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा बिहार में खूब गूंज रहा है। लेकिन मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए चिराग बिहार का चुनाव लड़ने को बेताव हैं तो इसके पीछे की राजनीति कोई मामूली नहीं होगी।

बीजेपी चिराग को तभी आगे बढ़ने का रिस्क ले सकती है जब चिराग यह कह दे कि वहज न तो एनडीए से बाहर जायेंगे और न ही नीतीश का समर्थन ही करेंगे। ये बातें इसलिए कही जा रही है कि अब नीतीश कुमार के साथ चिराग के रश्ते काफी मजबूत और सहज हो गए हैं। जदयू की सोंच और समझ भी चिराग को लेकर बदल गई है। और नीतीश तो यहाँ तक चाहते हैं कि अगर जदयू इस चुनाव में भी कमजोर होती है तो चिराग को आगे बढ़ाया जा सकता है। चिराग को सीएम भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये तमाम बातें भविष्य की गर्भ में है। राजनीति में कब क्या हो जाए और कब किसके रिश्ते बिगड़ जाए और बन जाए कोई नहीं जानता।

अब जरा चिराग की रणनीति पर नजर डालें तो पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बीते दिनों बिहार लौटने और विधानसभा चुनाव लड़ने के इरादे की घोषणा की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने राज्य के शीर्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चिराग, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "हनुमान" के रूप में पेश करते हुए अकेले चुनाव लड़ा था, ने पार्टी की सीटों को सहयोगी भाजपा की संख्या के लगभग आधे तक लाने में भूमिका निभाकर नीतीश की जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। इस बार एलजेपी सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा है, और कई लोग चिराग के इस कदम को सीटों के बंटवारे में जेडीयू को कमतर आंकने के प्रयास के रूप में देखते हैं।

क्या झारखंड के चाईबासा कोर्ट में हाजिर होंगे राहुल गांधी ?

न्यूज़ डेस्क

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट को निरस्त करने की मांग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चाईबासा कोर्ट ने वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में 22 मई को राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने सीआरपीसी की धारा 205 के अंतर्गत हाईकोर्ट में पहले से दायर की गई याचिका अब तक लंबित है। जब तक लंबित याचिका पर सुनवाई नहीं होती, तब तक चाईबासा कोर्ट की ओर से वारंट जारी करना अनुचित है।

प्रताप कटियार ने दर्ज कराई थी शिकायत

चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस के लोग किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है। इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

जून माह में इन सब्जियों की खेती से होगा लाभ

कृषि डेस्क

किसान सब्जियों की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सब्जियों की खेती करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कम समय में तैयार हो जाती है और इनका बाजार भाव भी अच्छा मिल जाता है। खरीफ व रबी सीजन के बीच जब खेत खाली रहते हैं तब किसान सब्जियों की खेती करके अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। आज हम आपको जून माह में उगाई जाने वाली टॉप 10 सब्जियों की खेती के बारे में बता रहे हैं जो आपको बंपर मुनाफा दिला सकती है, तो आइये जानते हैं कौनसी है ये टॉप 10 सब्जियां जिनसे बेहतर लाभ हो सकता है।

1. करेला की खेती

करेला की खेती करके किसान काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। करेले की फसल 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है और इसके भाव भी अच्छे मिल जाते हैं। शुगर और डायबिटीज के मरीजों के लिए तो इसका सेवन काफी लाभकारी माना जाता है। करेले की सब्जी के अलावा इसका रस का भी सेवन किया जाता है। यदि आप करेले की खेती करते हैं तो आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। करेले की हाइब्रिड किस्म से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कई उन्नत किस्में भी अच्छा उत्पादन देती है। इसकी हाइब्रिड किस्मों में पूसा हाइब्रिड-1 और पूसा हाइब्रिड-2 काफी अच्छी किस्में मानी गई हैं जो अधिक पैदावार देती हैं। ये किस्में 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। करेले की इन हाइब्रिड किस्मों से 70 से लेकर 80 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार प्राप्त की जा सकती है। आमतौर पर बाजार में करेले का भाव 20 से लेकर 30 रुपए किलोग्राम तक होता है। यदि एक एकड़ में इसकी खेती की जाए तो करीब 40,000 रुपए का खर्च आता है और मार्केटिंग अच्छी हो तो इससे डेढ़ लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है।

2. गिलकी की खेती

गिलकी में आयरन, पोटेशियम और विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। इसका सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। गिलकी की खेती खरीफ और जायद दोनों सीजन में की जा सकती है। इसकी खेती जीवांश युक्त सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। लेकिन खेत में अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि इसकी अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6-7 के बीच होना चाहिए। इसकी आलोक और वाणी किस्में काफी अच्छी हैं। लेकिन किसानों को अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्म का चयन करना चाहिए। इसके भी बाजार में अच्छे भाव मिल जाते हैं। आमतौर पर इसका बाजार भाव 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल जाता है।

3. लौकी की खेती

लौकी की खेती भी किसानों के लिए लाभकारी है। लौकी एक ऐसी सब्जी है जिससे सब्जी के अलावा भी बहुत से चीजें बनाई जाती है जिसमें लौकी का हलवा, लौकी का रायता, लौकी कबाब आदि कई डिश इससे बनाई जाती है। बीमारी में डॉक्टर अक्सर लौकी की सब्जी खाने की सलाह देते हैं क्योंकि ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। इसकी कई किस्में हैं जिनमें अर्का नूतन, अर्का श्रेयस, पूसा संतुष्टि, पूसा संदेश, अर्का गंगा, अर्का बहार आदि किस्में अच्छी हैं। लौकी फसल 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 32 से 58 टन प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है।

4. तोरई की खेती

तोरई की खेती साल में दो बार की जा सकती है। ग्रीष्म ऋतु में इसे जायद फसल कहा जाता है तथा खरीफ सीजन में भी इसे उगाया जाता है। इस तरह साल में दो बार इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन बारिश के समय इसकी खेती काफी अच्छी मानी जाती है। कच्ची तोरई की सब्जी बनाई जाती है जो सेहत के लिए काफी अच्छी होती है। वहीं इसके सूखे बीजों से तेल निकाला जाता है। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, पूसा सुप्रिया, काशी दिव्या, कल्याणपुर चिकनी आदि अच्छी किस्में हैं। तोरई के बीजों की रोपाई के 70 से 80 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है। इसकी उन्नत किस्मों से 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्राप्त होती है।

5. सेम की खेती

सेम की खेती के लिए दोमट, चिकनी व रेतीली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होना जरूरी है। क्षारीय व अम्लीय भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। इसकी उन्नत किस्मों में पूसा अर्ली, काशी हरितमा, काशी खुशहाल (वी.आर. सेम-3), बी.आर. सेम-11, पूसा सेम-2, पूसा सेम-3, जवाहर सेम-53, जवाहर सेम-79 आदि अच्छी किस्में हैं। इसकी उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टेयर करीब 100 से 150 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

6. मेथी की खेती

मेथी की सब्जी और दाना मेथी का प्रयोग मसाले में किया जाता है। इसकी खेती हरे रूप में पत्तों के लिए और सूखे रूप में इसके दानों के लिए की जाती है। हरी मेथी की सब्जी बनाई जाती है, जबकि दानों का उपयोग मसाले के तौर पर किया जाता है। मेथी की उन्नत किस्मों में कसूरी मेथी, पूसा अर्ली बंचिंग, यूएम 112, कश्मीरी, हिसार सुवर्णा आदि हैं। इसकी फसल 20 से 25 दिन में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं बीज प्राप्त करने के लिए इसकी कटाई बिजाई के 90 से 100 दिन बाद करनी चाहिए। यदि इसकी एक बार कटाई के बाद बीज लिया जाए तो इसकी औसत पैदावार 6-8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। वहीं 4-5 कटाइयां होने पर पैदावार घटकर करीब 1 क्विंटल तक रह जाती है। वहीं भाजी या हरी पत्तियों की पैदावार करीब 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है।

7. पालक की खेती

पालक की खेती कम खर्च में अधिक कमाई देने वाली सब्जी है। यह कम समय में तैयार हो जाती है। पालक की फसल बुवाई के 25 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। करीब 10-15 दिन बाद यह दोबारा कटाई के लायक हो जाती है। इसकी 5 से 6 कटाई करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। पालक की कई उन्नत किस्में हैं जिनमें जोबनेर ग्रीन, पूसा पालक, पूसा ज्योति, पूसा हरित, लांग स्टैंडिंग, पंत कंपोजिटी आदि किस्में काफी अच्छी है। इसकी उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टेयर 150 से लेकर 250 क्विंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है।

8. धनिया की खेती

धनिया की खेती गर्मी के मौसम में की जा सकती है। इसकी खेती से करीब प्रति बीघा 90 हजार रुपए की कमाई की जा सकती है। गर्मियों में हरे धनिये का भाव काफी बढ़ जाता है।

हल्दी की जैविक खेती से किसानों को होगा मुनाफा

कृषि डेस्क

जैविक हल्दी की खेती न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय भी साबित हो सकता है। जैविक खेती पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ तरीका है। खेती के इस तरीके में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता। हल्दी की खेती न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय भी साबित हो सकता है।हल्दी, जिसे भारतीय केसर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती से किसान जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। यह भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा है, जिसके कारण यह सालभर डिमांड में बनी रहती है। बल्कि इसके औषधीय गुणों के कारण वैश्विक स्तर पर भी लोकप्रिय है। जैविक हल्दी की खेती न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय भी साबित हो सकता है।

हल्दी की जैविक खेती के लिए इन बातों का रखें ध्यान

मिट्टी और जलवायु की तैयारी : हल्दी की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करें। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए।

जलवायु : इसके लिए 20-30 डिग्री सेल्सियस जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद (गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट, नीम खली) का इस्तेमाल करें।

हल्दी की गांठ का चयन

हमेशा स्वस्थ, रोगमुक्त और जैविक रूप से उगाई गई हल्दी की गांठ का चुनाव करें। गांठें मध्यम आकार की और 2-3 आंखों (कलियों) वाली होनी चाहिए। बुवाई करने से पहले गांठों को गोमूत्र या जैविक फफूंदनाशक से उपचारित करें।

खेत को करें तैयार

खेतों की जुताई करने के बाद जैविक खाद डालें। इसके बाद 30-45 सेमी की दूरी पर मेड़ (रिज) बनाएं। खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

बुआई का समय

भारत में हल्दी की बुआई मई-जून के बीच की जाती है। पंक्तियों के बीच 30-45 सेमी और पौधों के बीच 15-20 सेमी की दूरी रखें। गांठों को 5-7 सेमी गहराई में बोएं। एक हेक्टेयर ज़मीन में 20-25 क्विंटल गांठों की आवश्यकता होती है।

सिंचाई का समय

हल्दी की फसल को नमी की आवश्यकता होती है। मानसून में अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत नहीं, लेकिन शुष्क मौसम में 7-10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। सिंचाई के लिए ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल करें।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान -

बुआई के 30-60 दिन बाद खरपतवार हटाने के लिए हल्की निराई-गुड़ाई करें।समय पर कीट और रोग प्रबंधन करने से उत्पादन बढ़ सकता है।फसल चक्र अपनाएं (हल्दी के बाद मूंग, चना या अन्य फसलें उगाएं)।हल्दी 7-9 महीने में पककर तैयार होती है। जब पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगें, तब कटाई करें।

ठग लाइफ' : फिल्म समीक्षा कहानी और भाषा विवाद

आईपीएस यादव

मणि रत्नम की 'ठग लाइफ' एक गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें कमल हासन और सिलंबरासन टीआर की जोरदार टक्कर दर्शकों को बांधे रखने का वादा करती है, लेकिन कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी ने कर्नाटक में फिल्म की रिलीज को खतरे में डाल दिया है। मणि रत्नम द्वारा निर्देशित और कमल हासन अभिनीत 'ठग लाइफ' 5 जून, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली एक बहुप्रतीक्षित तमिल गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म कमल हासन और मणि रत्नम की 1987 की क्लासिक 'नायकन' के बाद पहली सहयोगी फिल्म परियोजना है। हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले कमल हासन की कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति पर की गई टिप्पणी ने कर्नाटक में विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके कारण फिल्म पर प्रतिबंध की धमकी दी गई है।

क्या है ठग लाइफ की कहानी ?

'ठग लाइफ' एक गैंगस्टर ड्रामा है, जिसकी कहानी कमल हासन के मूल स्क्रिप्ट 'अमर है' पर आधारित है। फिल्म में कमल हासन रंगराया सक्तिवेल नायकर नामक एक गैंग लीडर की भूमिका में हैं, जो एक जटिल और बहुस्तरीय किरदार है। कहानी एक अनाथ बच्चे अमरन (सिलंबरासन टीआर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे सक्तिवेल एक गैंग युद्ध के दौरान बचाता है और उसे अपने संरक्षण में लेता है। वर्षों बाद, सक्तिवेल पर हत्या का प्रयास होता है, और उसे संदेह होता है कि इसमें अमरन का हाथ हो सकता है। यह विश्वासघात और वफादारी का संघर्ष कहानी का केंद्र बनता है, जिसमें भावनात्मक गहराई और तीव्र एक्शन का मिश्रण है।

ट्रेलर में कमल हासन के किरदार को कई समय रेखाओं में अलग-अलग लुक में दिखाया गया है, जो उनके किरदार के अतीत की जटिलता को दर्शाता है। एक प्रमुख दृश्य में सिलंबरासन का किरदार कहता है, "अब से मैं रंगराया सक्तिवेल हूँ," जो कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करता है। ट्रेलर में दक्षिण तमिलनाडु की बोली और याकुजा (जापानी गैंगस्टर) जैसे संदर्भों का उपयोग कहानी को एक अनूठा आयाम देता है, जो ऐतिहासिक, समकालीन या काल्पनिक सेटिंग का मिश्रण हो सकता है। कहानी में सक्तिवेल और अमरन के बीच एक पिता-पुत्र जैसा रिश्ता विकसित होता है, जो बाद में वैचारिक और भावनात्मक टकराव में बदल जाता है। फिल्म में सक्तिवेल के जीवन में एक रहस्यमयी मोड़ भी है, जहां उसे मृत मान लिया जाता है, लेकिन वह जीवित लौटता है, जिससे माफिया संघर्ष और गहन नाटक शुरू होता है। इसमें शक्ति, विश्वासघात और मोचन के थीम्स का गहरा चित्रण है, जो मणि रत्नम की कहानी कहने की शैली को और मजबूत करता है। स्टार कास्ट में त्रिशा कृष्णन, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अशोक सेलवन, जोजू जॉर्ज, नासर, अली फजल, पंकज त्रिपाठी, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा शामिल हैं, जो फिल्म को एक पैन-इंडिया अपील देते हैं। ए.आर. रहमान का संगीत, रवि के. चंद्रन की सिनेमैटोग्राफी और श्रीकर प्रसाद का संपादन फिल्म की तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ाते हैं।

भाषा विवाद

'ठग लाइफ' के ऑडियो लॉन्च इवेंट में 24 मई, 2025 को चेन्नई में कमल हासन ने कन्नड़ सुपरस्टार शिवराजकुमार की तारीफ करते हुए कहा, "आपका भाषा (कन्नड़) तमिल से जन्मी है।" इस टिप्पणी ने कर्नाटक में तीव्र विवाद को जन्म दिया, क्योंकि कई कन्नड़ भाषी समुदायों और सांस्कृतिक संगठनों ने इसे कन्नड़ भाषा की स्वतंत्र विरासत को कम करने वाला माना। कर्नाटक रक्षना वेदिके जैसे समूहों ने बेंगलुरु, मैसूरु, हुबली और बेलगावी में विरोध प्रदर्शन किए, फिल्म के पोस्टर फाड़े और कमल हासन की मूर्तियों को जलाया।

कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 30 मई तक कमल हासन से माफी मांगने की मांग की, धमकी दी कि बिना माफी के 'ठग लाइफ' की रिलीज को कर्नाटक में रोका जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 3 जून, 2025 को सुनवाई के दौरान कमल हासन की आलोचना की, यह पूछते हुए, "क्या आप इतिहासकार या भाषाविद् हैं?" और कहा कि एक माफी से विवाद खत्म हो सकता था। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाया, यह उल्लेख करते हुए कि भाषा और संस्कृति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी टिप्पणियाँ अशांति पैदा करती हैं। विवाद ने कर्नाटक में फिल्म की रिलीज को अनिश्चित कर दिया है, जो दक्षिण भारतीय फिल्म बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि प्रतिबंध से निर्माताओं को 50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति पर बहस ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तनाव को उजागर किया है, विशेष रूप से तमिल और कन्नड़ समुदायों के बीच, जो पहले भी कावेरी नदी विवाद जैसे मुद्दों पर भिड़ चुके हैं।

मणि रत्नम और कमल हासन की धमाकेदार वापसी

मणि रत्नम और कमल हासन की जोड़ी 38 साल बाद 'ठग लाइफ' के साथ लौटी है, और यह फिल्म उनकी 1987 की कालजयी 'नायकन' की विरासत को नया आयाम देती है। यह गैंगस्टर ड्रामा शक्ति, विश्वासघात और मोचन की कहानी है, जिसमें कमल हासन का रंगराया सक्तिवेल नायकर एक ऐसा गैंगस्टर है, जिसका अतीत और वर्तमान टकराते हैं। सिलंबरासन टीआर का किरदार अमरन, जो उनके द्वारा पाला गया अनाथ है, कहानी को एक भावनात्मक और वैचारिक टकराव की ओर ले जाता है। दोनों अभिनेताओं की स्क्रीन मौजूदगी और टकराव दृश्यों में गजब की तीव्रता है, जो दर्शकों को बांधे रखती है। मणि रत्नम की कहानी कहने की शैली इस फिल्म में अपने चरम पर है। उनकी सिग्नेचर गहराई, रवि के. चंद्रन की शानदार सिनेमैटोग्राफी और ए.आर. रहमान का इलेक्ट्रिफाइंग संगीत फिल्म को एक दृश्य और भावनात्मक उत्सव बनाता है। 'सुगर बेबी' जैसे गाने पहले ही चार्टबस्टर बन चुके हैं। हालांकि, कहानी में 'गॉडफादर' और 'नायकन' जैसे क्लासिक्स की छाया दिखती है, मणि रत्नम इसे अपने अनूठे अंदाज में नया रंग देते हैं। कमल हासन कई समय रेखाओं में अलग-अलग लुक के साथ अपने किरदार की जटिलता को बखूबी दर्शाते हैं, जबकि सिलंबरासन का तीव्र अभिनय फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। त्रिशा और अभिरामी के रोमांटिक दृश्यों ने कुछ ऑनलाइन बहस छेड़ी है, लेकिन ये कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। पंकज त्रिपाठी और अली फजल जैसे बॉलीवुड सितारे पैन-इंडिया अपील को मजबूत करते हैं। हालांकि, कर्नाटक में भाषा विवाद ने फिल्म की रिलीज पर सवाल उठाए हैं। यह विवाद फिल्म की सामग्री से नहीं, बल्कि कमल हासन की टिप्पणी से जुड़ा है, जो दर्शकों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। 'ठग लाइफ' एक ब्लॉकबस्टर अनुभव है, जो एक्शन, ड्रामा और भावनाओं का शानदार मिश्रण है। यह सिनेमाघरों में देखने लायक है, खासकर मणि रत्नम और कमल हासन के प्रशंसकों के लिए।

अर्जुन की फिल्म में सेट हो गईं दीपिका इतने करोड़ में डील हुई फाइनल

फ़िल्मी डेस्क

दीपिका पादुकोण इस वक्त फिल्मों में अपनी वापसी को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस दौरान उनका नाम कई फिल्मों के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका अल्लू अर्जुन की फिल्म AA22xA6 के लिए डील साइन कर चुकी हैं और उनकी फीस भी डिसाइड हो गई है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म काफी चर्चा बटोर रहा है। एटली के साथ एक्टर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जाह्नवी कपूर के शामिल होने की खबर है। प्रेग्नेंसी के बाद से एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार हो चुकी हैं। हाल ही में आ रही खबर में ये सामने आ रहा है कि दीपिका ने इस फिल्म को ऑफिशियल साइन कर दिया है।

दीपिका पादुकोण की जब से फिल्मों में वापसी की खबर सामने आई है, तभी से उनका नाम कई सारे प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल एक्ट्रेस का नाम अल्लू अर्जुन की फिल्म के साथ जोड़ा जा रहा है। फेमस फिल्ममेकर एटली की डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल AA22xA6 रखा गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म में 3 एक्ट्रेस शामिल होंगी। खबरों में बताया जा रहा है कि कई महीनों से दीपिका और एटली की इस फिल्म को लेकर बातचीत हो रही थी।

कितनी ले रही हैं फीस?

700 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म में दीपिका की फीस को लेकर भी चर्चा बढ़ गई है। मिड-डे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस इस फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपए फीस के तौर पर ले रही हैं। अब लोग जल्द ही इस फिल्म का फील्ड पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, पहले वो शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' की शूटिंग पूरी करेंगी। किंग साल 2026 में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म से शाहरुख की बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू करने जा रही हैं।

स्पिरिट में भी आया था नाम

हालांकि, शाहरुख और अल्लू अर्जुन की फिल्मों के साथ ही साथ एक्ट्रेस का नाम प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' में भी जोड़ा जा रहा था। लेकिन, बाद में खबर आई कि संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म से दीपिका बाहर आ चुकी हैं। एटली के साथ दीपिका की ये दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों ने 'जवान' में साथ काम किया था.हालांकि, फिल्मों में दीपिका की वापसी के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं।

बिहार का पहला फिल्म सेट- स्टूडियो तैयार, 14 फिल्मों की शूटिंग को मंजूरी

फ़िल्मी डेस्क

लाइट, कैमरा, एक्शन...अब ये शब्द सिर्फ मुंबई या हैदराबाद तक सीमित नहीं रह गए हैं. बदलते बिहार की बदली हुई तस्वीर अब दिखने लगी है। जिन जंगलों में कभी लोग जाने से डरते थे आज सीएम नीतीश सरकार के प्रयासों के बाद उनकी खूबसूरती और हरियाली से प्रभावित होकर देश के जाने माने फिल्म निर्देशक अपनी फिल्मों की शूटिंग करने पहुंच गए हैं। बिहार फिल्मों की शूटिंगः राज्य सरकार फिल्म निर्माण को लेकर काफी उत्साहित है। बिहार में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन नीति का फायदा दिखने लगा है। बिहार में लगातार फिल्मों की शूटिंग हो रही है. बिहार में 14 फिल्मों को अब तक शूटिंग की मंजूरी दी गई है।

बिहार बना फिल्म शूटिंग का नया हॉटस्पॉट : नई फिल्म पॉलिसी के कारण बिहार फिल्मों की शूटिंग का नया हॉटस्पॉट बन गया है. भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, मगही से लेकर अंग्रेजी फिल्मों तक की शूटिंग अब बिहार की मिट्टी पर हो रही है। राज्य में अब तक जिन 14 फिल्मों को शूटिंग की अनुमति दी गई है। उनमें संघतिया, टिया, ओह माय डॉग, सेनापति, लाइफ लीला, सुगनी, छठ, पेन ब्रश, नारी, बिहार का जलवा जैसी फिल्में शामिल हैं. कुछ की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि कई पर कार्य जारी है. फिल्मों की शूटिंग बिहार के नालंदा, नवादा, गया, पटना, बगहा, रोहतास, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और जहानाबाद जैसे जिलों में की जा रही है। इससे इन जिलों को पर्यटक और स्थानीय व्यवसाय की दृष्टि से लाभ मिल रहा है।

पहला फिल्म सेट और स्टूडियो

बिहार अब स्थायी फिल्म निर्माण संबंधी संरचनाएं भी विकसित कर रहा है। वाल्मीकि नगर में राज्य का पहला फिल्म सेट बन रहा है, जहां सागर श्रीवास्तव की हिंदी फिल्म 'टिया' की शूटिंग हो रही है। इसके अलावा जहानाबाद के काको स्थित पाली में हैदर काजमी स्टूडियो स्थापित हुआ है, जहां कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। काजमी खुद एक चर्चित अभिनेता और निर्देशक हैं।

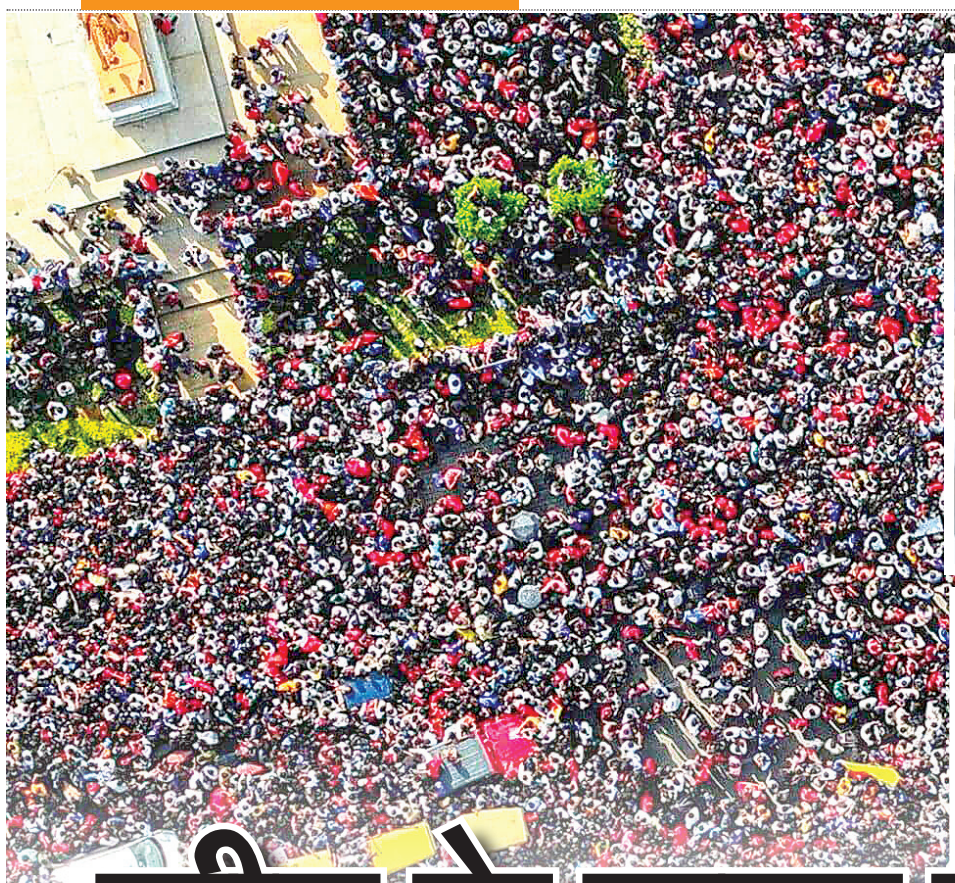

जीत के जश्न में मौत का मातम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक आईपीएल जीत का जश्न स्टेडियम के अंदर चरम पर था, लेकिन बाहर भगदड़ ने 11 लोगों की जान ले ली, जिससे बचे हुए लोग और परिवार सदमे में हैं।

खेल डेस्क

4 जून 2025 को बेंगलुरु ने उत्सव और त्रासदी का एक दुखद मिश्रण देखा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 18 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए 3 जून को आईपीएल फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर खिताब जीता। हालांकि, चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास आयोजित विजय परेड में भगदड़ मच गई, जिसमें 13 से 33 साल की उम्र के 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। 35,000 की क्षमता वाले इस स्टेडियम के आसपास 3 लाख से ज्यादा प्रशंसक जमा हो गए थे।

जीत का जश्न और बाहर मातम

स्टेडियम के अंदर, आरसीबी की जीत कप्तान विराट कोहली के लिए एक सपना सच होने जैसा था, जिनकी आंखें जीत के बाद नम हो गईं। "मैंने सोचा नहीं था कि यह दिन कभी देखने को मिलेगा," कोहली ने 18 साल के अपने सफर को याद करते हुए कहा। लेकिन बाहर, खुशी जल्द ही मातम में बदल गई। कुछ लोग उत्सव के लिए आए थे, तो कुछ सिर्फ मौज-मस्ती के लिए। शामिली नाम की एक युवती, जो अपनी बहन और दोस्तों के साथ सिर्फ मस्ती के लिए आई थी, ने बताया, "मैं तो फैन भी नहीं हूं। मैंने अपनी बहन से कहा कि चलो यहां से, बहुत धक्का-मुक्की हो रही है। अचानक मैं जमीन पर गिर गई और भीड़ में कुचल गई। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी।" शामिली को असहनीय पेट दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने इसे मांसपेशियों का दर्द बताया, लेकिन वह अभी भी डरी हुई है।

बेकाबू भीड़ और पुलिस की नाकामी

पुलिस का अनुमान था कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन भीड़ 3 लाख के पार पहुंच गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 2 लाख लोग जमा हो गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्टेडियम और विधान सौध के आसपास भीड़ "उन्मादी" हो गई थी। विधान सौध में गवर्नर थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरसीबी खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। लेकिन बाहर हालात बेकाबू हो गए। हनीफ मोहम्मद, एक इंजीनियरिंग छात्र, ने कहा, "मैं सिर्फ भीड़ देख रहा था। अचानक लोग दौड़ने लगे और पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दीं। एक पुलिसवाले ने मेरे सिर पर लाठी मार दी।" हनीफ को सिर पर चोट लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कॉमर्स के छात्र मनोज ने बताया कि एक पुलिस बैरिकेड उनके पैर पर गिर गया, जिससे वह घायल हो गए।

मृतकों के परिवारों तक पहुंचने में मुश्किल

भगदड़ में मारे गए 11 लोगों में सबसे कम उम्र की 13 साल की दिव्यांशी थी। एक सरकारी डॉक्टर ने कहा, "इतना छोटा बच्चा ऐसी भीड़ में क्या कर रहा था, समझना मुश्किल है।" मृतकों में 17, 20, 25, 27 और 33 साल के लोग शामिल थे। पुलिस अभी तक कई मृतकों के परिवारों से संपर्क नहीं कर पाई है। एक पुलिसकर्मी ने बताया, "मारे गए लोग बेंगलुरु के नहीं थे। वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलग-अलग जिलों से थे। उनके फोन या तो खो गए या चुरा लिए गए।" अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि ज्यादातर लोग पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे, दम घुटने और पसलियां टूटने से उनकी मौत हुई।

प्रशासन पर सवाल और जांच के आदेश

जब स्टेडियम के अंदर जश्न हो रहा था, बाहर जिंदगी ठहर गई थी। एक घायल के रिश्तेदार ने कहा, "ऐसे आयोजनों में भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी था, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी।" मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "खुशी का मौका गम में बदल गया।" उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 2023 की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि स्टेडियम की क्षमता से 20% ज्यादा भीड़ खतरनाक हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी की गई।

18 साल का इंतजार और कोहली का सपना

आरसीबी की जीत का जश्न स्टेडियम में चरम पर था। 2008 में आईपीएल की शुरुआत से चला आ रहा यह इंतजार 3 जून 2025 को खत्म हुआ। फाइनल में पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में जब शशांक सिंह बाउंड्री नहीं लगा पाए, तो कोहली की आंखें नम हो गईं। जीत के बाद कोहली घुटनों पर बैठ गए और भावुक होकर बोले, "मैंने अपनी जवानी, अपना अनुभव, सब कुछ दिया। मेरा दिल बेंगलुरु के साथ है।" 2008 में 20 लाख रुपये में खरीदे गए कोहली ने 2011 में कप्तानी संभाली और 2016 में रिकॉर्ड 973 रन बनाए। 2025 में उन्होंने 657 रन बनाकर आखिरकार अपने सपने को पूरा किया।

गेल और डिविलियर्स के साथ साझा की ट्रॉफी

जीत के बाद कोहली ने पूर्व खिलाड़ी क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स के साथ ट्रॉफी साझा की। गेल ने आरसीबी के लिए 3163 रन और 248 छक्के, जबकि डिविलियर्स ने 4491 रन और 237 छक्के बनाए। कोहली ने कहा, "यह जीत जितनी मेरी है, उतनी इनकी भी है।" 2011 और 2016 में फाइनल तक पहुंची टीम का हिस्सा रहे गेल और डिविलियर्स मैदान पर कोहली से गले मिले। गेल ने 2013 में नाबाद 175 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया था, जो आज भी बरकरार है। कोहली ने कहा, "इनके बिना यह जीत अधूरी होती।"

राजीव शुक्ला होंगे बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष

खेल संवाददाता

अनुभवी क्रिकेट प्रशासक राजीव शुक्ला अगले महीने 70 साल के होने वाले रोजर बिन्नी की जगह अंतरिम बीसीसीआई अध्यक्ष बनने को तैयार हैं, बीसीसीआई सूत्रों ने यह जानकारी दी है। 65 वर्षीय शुक्ला वर्तमान में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, वह 2020 से इस पद पर हैं। बता दें कि 2022 में सौरव गांगुली की जगह बोर्ड अध्यक्ष बने बिन्नी 19 जुलाई को 70 साल के हो जाएंगे, जो बीसीसीआई पदाधिकारी के लिए आयु-सीमा सीमा को पार कर जाएगा।

बीसीसीआई के सूत्र ने कहा, "परंपरा के अनुसार, इस तरह के परिदृश्य में सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यभार संभालते हैं। सितंबर में नए चुनाव होने तक वे (शुक्ला) उस भूमिका को निभाएंगे।" कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में, सी के खन्ना ने 2017 से 2019 तक बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने 33 महीने तक बोर्ड पर शासन किया था। तीन साल पहले दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालने से पहले बिन्नी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। खेल के महान खिलाड़ियों में गिने जाने वाले पूर्व ऑलराउंडर कपिल देव के नेतृत्व में 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। बाद में वह भारत की अंडर-19 टीम के कोच बने, जिसने 2000 में इसी आयु वर्ग में आईसीसी विश्व कप जीता था।